घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 266- सोमवार 27- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पेपरलीक रोकने के लिए कठोर कानून लाएंगे : पीएम मोदी

परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स बनाई इंफोसिस को-फाउंडर नीलेकणी अध्यक्ष होंगे...

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स का गठन किया। टीम में छह मेंबर्स हैं। इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। पीएम ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी कर इसकी जानकारी दी। पिछले 4 दिनों में यह इंस्टाग्राम पर मोदी का तीसरा वीडियो मैसेज है। पीएम ने कहा- स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाईपावर टॉस्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। जो एग्जॉमिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।

दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। दिल्ली सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर निर्मल जैन और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर लता गुप्ता की नियुक्ति की है। यह जानकारी रविवार को दिल्ली सरकार की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई है। दिल्ली सरकार ने निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्य नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष निर्मल जैन एवं सदस्य को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र को सशक्त करते हुए समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे तथा सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास को नई ऊर्जा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नियुक्तियां समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष तथा श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरक्षिका शर्मा झा एवं रेनू भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी दिल्ली सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, अधिकारों और सशक्तिकरण को नई दिशा देंगी तथा एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सुरक्षित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में दिल्ली महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता को नई गति मिलेगी तथा महिलाओं तक न्याय, संरक्षण और सहायता की पहुंच और अधिक प्रभावी होगी।

कॉकरोच जनता पार्टी की अगली रणनीति जल्द बताएंगे : अभिजीत दीपके

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- 'आगे की रणनीति का ऐलान जल्द करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कल ही खत्म हुआ है। प्लीज हमें थोड़ा समय दें। जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में पेपर लीक को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर दीपके ने जवाब दिया कि उस पर भी बात करेंगे। हम अभी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सरकार के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा कि जो केस फाइल किए गए हैं, उनके बारे में बात चल रही है। किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 20 जून से जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चला आंदोलन 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। अभिजीत दीपके रविवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वहां से निकलकर उन्होंने यही बताया कि सरकार से बात चल रही है कि किसी भी स्टूडेंट पर केस न किया जाए। अभिजीत की कपिल सिब्बल से मुलाकात, उनसे लीगल एडवाइज लेने के तौर पर देखी जा रही है। सिब्बल भारत के सबसे सीनियर वकीलों में गिने जाते हैं, और पिछले चार दशक से ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

होर्मुज में तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराया...जहाज में आग लगी

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान,26 जुलाई 2026। होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर समुद्री माइन से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, यह टैंकर तेहरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से अलग रास्ते से जा रहा था, जिसके बाद वह बारूदी सुरंग से टकरा गया। ईरान पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से तय किए गए मार्ग से हटकर चलेगा, तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी उसी की होगी। फिलहाल इस घटना पर ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। नुकसान या हताहतों को लेकर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि इस तरह कोई जहाज समुद्री नेवल माइन से टकराया हो। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने यह समुद्री माइन बिछाई थी, जिसे सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हटाने का आदेश दिया था।

युवाओं ने देश का मान बढ़ाया...यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था : पीएम मोदी

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। पीएम मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस ऐसी तारीख है, जिसे याद रखने के लिए दिन याद रखने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने देश के युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा- हमारे युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।

साइंस ओलंपियाड दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स , कैमेस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड हुए। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा- पिछले रविवार विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। हम सभी ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के इस ऐतिहासिक पल को देखा। यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वह कर दिखाया, जो कभी लगभग असंभव लगता था। उन्होंने अपने असाधारण कौशल, जुनून और धैर्य का परिचय दिया।

मोदी बोले-12 सालों में खादी की बिक्री छह गुना बढ़ी : पीएम ने कहा- कुछ दिनों बाद देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। हाथ से बने उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों के हुनर और मेहनत का प्रतीक हैं। आज पोचमपल्ली, पटना और कच्छ जैसे क्षेत्रों के हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और इसकी बिक्री छह गुना बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने लोगों से खादी खरीदने की अपील की। साथ ही त्रिपुरा के सूरज कुमार देव वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पारंपरिक चोंग पैंग वाद्य यंत्र और त्रिपुरा के अन्य लोक वाद्य यंत्रों को फिर से लोकप्रिय बनाने का काम किया है। कार्यक्रम के अंत में मोदी ने कहा कि 27 जुलाई को भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि,इसी सप्ताह गुरु पूर्णिमा और कुछ ही सप्ताह बाद स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले लोगों को याद करना चाहिए और 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही लोगों से भविष्य के 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजते रहने की अपील भी की।

पीएम बोले- युवा इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था

पीएम ने कहा कि पिछले रविवार विक्रम-1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) द्वारा विकसित रॉकेट है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश के युवा इनोवेटर्स को देते हुए कहा कि उन्होंने वह कर दिखाया, जो कभी लगभग असंभव माना जाता था। मोदी ने कहा कि युवा इनोवेटर्स ने अपने कौशल, जुनून और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी और युवाओं की क्षमता का मजबूत उदाहरण है।

पीएम ने मिट्टी से बने गणेश की पूजा करने की अपील की

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 'मन की बात' में उन्होंने लोगों से मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पीओपी और प्लास्टिक की मूर्तियों से बचना चाहिए। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करना प्रकृति की भी पूजा है। मोदी ने मणिपुर के वैज्ञानिक डॉ. रोनाल्डो मीनांशम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने युवा आकाशगंगाओं (यंग गैलेक्सीज) की खोज की है। उन्होंने इस नई आकाशगंगा का नाम 'लोकटक प्रोटोक्लस्टर' रखा,जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर है। इससे मणिपुर का नाम दुनियाभर में पहुंच रहा है।

भारतीय जवानों ने चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस ऐसी तारीख है,जिसे याद रखने के लिए दिन याद रखने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी और देश को जीत दिलाई। मोदी ने बताया कि इस बार दिल्ली से द्रास तक विशेष शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने स्वदेशी रक्षा तकनीक का जिक्र करते हुए कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हुआ है और इसी साल पिनाका मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया।

पीवी सिंधु और संस्कृत पढ़ाने के नए तरीके की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा...कुछ दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं और पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। पीवी सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हमारी महिला टीम ने 200 रनों से पहला महिला टेस्ट जीता था। मोदी ने केरल के एर्नाकुलम की एक महिला टीचर की सराहना की,जो फुटबॉल के नियमों और मैचों की घटनाओं के जरिए बच्चों को संस्कृत सिखा रही हैं।

सिद्धारमैया का ऐलान : 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा,राजनीति भ्रष्ट हो गई...

दो महीने पहले सीएम पद छोड़ा था,शिवकुमार नए मुख्यमंत्री बने...

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने कहा है कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि,वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने शनिवार को मंड्या जिले के के.आर. पेट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा- राजनीति अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह नहीं बची है। सिद्धारमैया ने कहा...मैं अब 79 साल का हो चुका हूं। हमारी सरकार का कार्यकाल अभी करीब डेढ़ साल बाकी है। तब तक मेरी उम्र 81-82 साल हो जाएगी। मेरी सेहत पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अब पहले जैसे उत्साह के साथ काम करना संभव नहीं है। सिद्धारमैया का यह बयान उनके सीएम पद छोड़ने के दो महीने बाद आया है। सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के निर्देश और रोटेशनल सीएम फॉर्मूले (दो या ज्यादा नेताओं के बीच 5 साल के कार्यकाल को बांटना) के तहत 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। वे 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री थे। उनके बाद डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया।

सिद्धारमैया बोले- 2028 में राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे होंगे...

सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा- वरुणा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर मुझ पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले जब मैं चुनाव लड़ता था, तब क्षेत्र के लोग हमें पैसे देते थे और हमारी जीत सुनिश्चित करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सिद्धारमैया ने कहा- अब ऐसा समय आ गया है कि चुनाव लड़ना हो तो नेताओं को ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 2028 तक मैं 82 साल का हो जाऊंगा। उस समय मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हो जाएंगे।

सिद्धारमैया बोले...अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया

पूर्व सीएम ने आगे कहा- मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया और न ही अपनी अंतरात्मा से समझौता किया। पिछले पांच दशकों से राज्य के लोगों ने मुझे अपना मानकर प्यार और मार्गदर्शन दिया है। उनका यह ऋण मैं हमेशा महसूस करता हूं। इसलिए मेरा आगे का जीवन भी जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के समय मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के कार्यकाल का फॉर्मूला चर्चा में रहा था। 20 नवंबर 2025 को सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे होने के बाद सत्ता परिवर्तन की मांग तेज हो गई। डीके शिवकुमार और उनके समर्थक कथित 'सीक्रेट डील' लागू करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन सिद्धारमैया लगातार इससे इनकार करते रहे।

पदभार संभालते ही एक्शन में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी,मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। रविवार को उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं,लंबित मामलों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन और छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में प्रह्लाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। प्रह्लाद जोशी इससे पहले केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस दौरान उन्हें संसदीय कार्य,कोयला और खान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने जून 2024 तक निभाई। वर्ष 2024 के आम चुनाव के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व दिया गया। अब शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पहले ही दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर यह संकेत दिया है कि मंत्रालय की प्राथमिक योजनाओं और नीतिगत कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राहुल बोले-स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया,शाह को चिट्ठी लिखी

नई दिल्ली,26 जुलाई 2026। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें राहुल ने दो सवाल पूछे हैं। पहला- प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा- सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, वे पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की। राहुल ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कइयों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। 19 साल के छात्र साहिल लोचब की एक आंख चली गई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पाटी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका जेपी नड्डा से मिले और उनके सामने देश में शिक्षा सुधार के लिए 5 मांगें रखीं। इनमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की सजा,दोषियों की संपत्ति जब्त करने, नया नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाने और नियुक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया।

असम : कछार में इंडस्ट्रियल यूनिट में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट,चार मजदूरों की मौत,कई अन्य घायल हुए...

असम,26 जुलाई 2026। असम के कछार जिले में रविवार को एक औद्योगिक इकाई में एलपीजी सिलेंडर में हुए विस्फोट में कम से कम चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएमसीएच) में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा उधारबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानग्राम स्थित खादी रोड इंडस्ट्रीज में हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर में हुआ विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास का इलाका दहल उठा। धमाके के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। बचावकर्मियों ने घायलों को मलबे और प्रभावित क्षेत्र से निकालकर तत्काल इलाज के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा। चिकित्सकों की टीम गंभीर रूप से घायल मजदूरों का उपचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार,कुछ घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जांच में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया।

पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बातचीत सिर्फ पीओके पर फोकस होगी : राजनाथ

द्रास,26 जुलाई 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 27वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास से देश को संबोधित किया। उन्होंने फिर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के भारत के इरादे और काबिलियत को दिखाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ़ पीओके पर फोकस होगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत तरक्की के लिए खड़ा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 'यह दिल मांगे मोर' की भावना कि भारत की संप्रभुता के विरुद्ध हर घृणित कृत्य का उसी दृढ़ता से जवाब से दिया जाएगा, जिस दृढ़ जवाब से भारतीय रक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को अद्वितीय वीरता के साथ दिया था। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों के बीच का अंतर मिट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना न केवल आतंकवादी संगठनों को शरण देती है, बल्कि उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब आतंकवादियों और उन्हें बढ़ावा देने वाली सरकारों को अलग-अलग इकाई के रूप में नहीं देखता। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रविवार को 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च कुर्बानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और साथ ही यह भी कहा कि भारतीय सेना के योद्धा दुनिया के किसी भी अन्य सैनिक से कहीं बेहतर और बेजोड़ हैं। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल सेठ ने कहा कि स्मारक का दौरा करने से उन्हें नई ऊर्जा और अपार गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कारगिल संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों की कुर्बानी के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। जनरल सेठ ने भारतीय सैनिकों के साहस, पेशेवर रवैये और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना का योद्धा दुनिया की किसी भी सेना के सैनिक से बेजोड़ है।

अब डिफेंस में आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के विज़न की ओर भारत के कदम को आगे बढ़ा रही है।कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा

संपादकीय

संस्थागत बीमारी है पेपर लीक

संसद का मानसून सत्र शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे समूह काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को कुछ अहमियत तब मिली,जब लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन प्रारंभ किया।

18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाकर भर्ती किया तो जंतर-मंतर पर भीड़ कुछ बढ़नी शुरू हुई। 20 जुलाई को संसद शुरू होने के दिन सीजेपी के संसद मार्च के पहले जंतर-मंतर पर अच्छी-खासी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब भीड़ को संसद की ओर जाने से रोका तो कुछ शरारती तत्वों ने उस पर पथराव करना और बैरिकेडिंग लांघना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को संसद की ओर जाने से रोकने के लिए जो सख्ती दिखाई, उसने यह बताया कि वह न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बना सकी। इस पर हैरानी नहीं कि उसकी सख्ती एक मुद्दा बन गई, लेकिन सच यह भी है कि भीड़ में कुछ तत्व पुलिस को निशाना बनाने की तैयारी से आए थे।

यह माहौल बनाना सही नहीं कि भीड़ ने कुछ नहीं किया और पुलिस ने बेवजह बल प्रयोग किया। आखिर घायलों में प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी भी हैं। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि अपने समर्थकों में कुछ अराजक तत्वों के घुस आने की बात सीजेपी प्रमुख ने भी मानी।

सीजेपी के संसद मार्च में हिंसा के बाद राजनीतिक दलों को सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया और वे उसे भुनाने के लिए एक-दूसरे से होड़ में लग गए। कांग्रेस ने जब यह देखा कि सीजेपी को महत्ता मिल रही है तो राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना देने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी को यह रास नहीं आया और उसने आपत्ति जताते हुए भाजपा-कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगा दिया। साफ है विपक्ष का रवैया छात्र हित के बहाने अपनी राजनीति चमकाने वाला अधिक रहा।

अनशन तोड़ चुके सोनम वांगचुक को खारिज कर रही कांग्रेस इससे चिंतित दिखी कि कहीं सीजेपी को समर्थन देना उसके लिए राजनीतिक रूप से हानिकारक न हो जाए। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की चिंता का एक कारण यह भी रहा कि नीट पेपर लीक मामले में उसके विरोध से अधिक महत्ता एक नए बने संगठन को मिल गई। यह उनकी चिंता का कारण बनना भी चाहिए, क्योंकि यह स्थिति जनता में उनके प्रति भरोसे की कमी को दिखाती है। विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की घोषणा को अपनी जीत बता सकते हैं, लेकिन यह सीजेपी के बैनर तले आए छात्रों के दबाव का नतीजा अधिक है।

शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र के पहले प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के साथ ही सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को और कठोर बनाने का फैसला किया। सरकार नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के स्वजनों को मुआवजा देने समेत संसद मार्च में हिंसा के आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की सीजेपी की मांग पर भी सहमत हो गई।

इसके बाद सीजेपी प्रदर्शन खत्म करने को तैयार हो गई,लेकिन यदि यह समझा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र से परीक्षा के मोर्चे पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह सही नहीं,क्योंकि पेपर लीक एक संस्थागत बीमारी है। यह बीमारी केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं। अब तो शिक्षक ही पेपर लीक कराने में शामिल पाए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि स्कूली परीक्षाओं में भी नकल होती है और इन परीक्षाओं के भी पेपर लीक किए और कराए जाते हैं।

नकल एक सामाजिक बुराई बन गई है। आज जो छात्र पेपर लीक मसले पर उग्र हैं, उनमें से अनेक यह जानते होंगे कि उनके कई साथी नकल करके पास होते रहे हैं। क्या सीजेपी यह मांग करेगी कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के दायरे में परीक्षाओं में नकल करने और कराने वाले भी लिए जाएं या फिर इसके लिए कोई नया कानून बनाया जाए?

सीजेपी के सदस्य और उनके समर्थक इससे अनजान नहीं हो सकते कि नकल कर पास होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? जो छात्र शुरू से धोखाधड़ी का सहारा लेकर पास होने का आदी रहा हो, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छल-कपट के सहारे पास होने की कोशिश करता है। कई बार तो अभिभावक और शिक्षक भी उनका साथ देते हैं। इसी कारण पेपर लीक का एक बाजार बन गया है। इसी बाजार के कारण पेपर लीक माफिया पैदा हो गया है, जिसमें कोचिंग चलाने वाले भी शामिल हैं। पेपर लीक माफिया परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिला लेता है।

इस बार तो उन शिक्षकों ने ही नीट के पेपर लीक कराए, जिनकी जिम्मेदारी इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की थी। ऐसे में कहना कठिन है कि पेपर लीक संबंधी कानून को और कठोर करने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान के लिए तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। आज के युग में पुराने तौर-तरीकों से परीक्षा कराने का औचित्य नहीं। तब तो और भी नहीं, जब तकनीक सुलभ है और वह कारगर भी साबित हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में इतनी अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं कि उनकी गिनती करना कठिन है। चूंकि कई केंद्रीय परीक्षाओं के साथ करीब-करीब सभी राज्यों की अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं,इसलिए राजनीतिक दल एक-दूसरे को कठघरे में खड़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते। उन्हें यह समझना होगा कि पेपर लीक समस्या का समाधान मिलकर करना होगा। उन्हें इस पर भी ध्यान देना होगा कि पेपर लीक का एक बड़ा कारण समाज का नैतिक पतन है और इस चारित्रिक पतन के लिए वे भी जिम्मेदार हैं।

यह नैतिक पतन ही परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है। क्या किसी सरकार या फिर राजनीतिक दलों अथवा सीजेपी के पास इस नैतिक पतन को रोकने का कोई उपाय है? यदि पेपर लीक मामले में संसद में बहस होती है तो क्या इस नैतिक पतन पर भी कोई बहस होगी? जब तक नैतिक मूल्यों के ह्रास की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तब तक परीक्षाओं में नकल होती रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी लीक होते रहेंगे।

पेपर लीक के आग उगलते दौर में प्रेरक है

आधुनिक जेन जेड बिहार के चंदन कुशाग्र के संघर्ष की कहानी

सुशील कुमार नवीन
हिसार,हरियाणा

13 वर्ष में 70 हजार रैंक से 7 हजार रैंक तक पहुंचने का सफर

पिछले एक सप्ताह से देश गंभीर दौर से गुजरा। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं (जेन जेड) के विश्वास को झाक झोरा। सड़कों पर आक्रोश दिखा, सोशल मीडिया ने खूब आग उगली। व्यवस्था की कमियों पर प्रश्न उठाना जितना आवश्यक रहा,दोषियों को कठोर दंड मिलना भी उतना ही और जरूरी रहेगा। एक इस्तीफे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी मंत्री का आना-जाना लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन संस्कृति और संस्कारों का क्षरण भी गंभीर चिंता का विषय है। इस पर भी चिंतन जरूरी है। युवा पीढ़ी की भाषा और व्यवहार में बढ़ती अशिष्टता वर्तमान समय में आत्ममंथन की मांग है। खैर जो हुआ सो हुआ। जो मिला वो अच्छा है, जो नहीं मिला वो भविष्य में मिलेगा या नहीं। इस पर चर्चाएं अभी बेमानी है।

जेन जेड के इस आंदोलन से इतर बिहार के नालंदा जिले के जोरारपुर गाँव के आधुनिक जेन जेड चंदन कुशाग्र की कहानी निराशा केभंवर में उलझे छात्र वर्ग के लिए एक नई उम्मीद का घोष है। पेपर लीक के ये भी पीड़ित हैं। प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना 'रश्मिरथी' की प्रसिद्ध पंक्तियां उनके संघर्ष पर बिल्कुल सटीक बैठती है

जीवन देकर जय खरीदना,
जग मे यही चलन है,
विजय दान करता न,
प्राण को रखकर कोई जन है.
मगर, प्राण रखकर प्रण,
अपना आज पालता हूँ मैं,
पूर्णाहुति के लिए विजय का
हवन डालता हूँ मैं।

उम्र रही होगी,बमुश्किल 8 से 10 वर्ष। जब स्कूल में टीचर ने स्वभाविक प्रश्न किया कि बेटा! बड़े होकर क्या बनोगे? बालमन से बिना सोचे,बिना विचारे तत्क्षण जवाब मिला। जी! मैं तो डाक्टर बनूंगा। डाक्टर ही क्यों बनोगे? इस बार जवाब हृदय को और झकझोरने वाला था। मेरे पापा चाहते हैं। और मैं उनकी यह इच्छा हर हाल में पूरी करूंगा। क्या कर पाओगे इतनी मेहनत? जवाब और भी हैरानी करने वाला था। पता है, सहज नहीं है,परंतु मैं प्रयत्न करूंगा। और उसने ये किया भी। हालात बिगड़ते रहे, परिस्थितियां विकट होती रहीं, परन्तु उसने हार नहीं मानी। 13 वर्ष से लगातार हर बार मेडिकल पात्रता परीक्षा दी। परिणाम विपरित रहे फिर भी निराशा को अपने उपर हावी नहीं होने दिया। और अंततः इस बार सफलता हाथ लग ही गई। 70

प्रकाशक: दैनिक घटती घटना

हजार से अधिक रैंक से शुरू सफलता के सोपान से अब 7 हजार की उच्चता के रैंक पर पहुंच गया है।

बिहार के नालन्दा जिले के एक छोटे से गांव जोरारपुर में जन्मे तीन बहन-भाईयों में सबसे बड़े 33वर्षीय चन्दन की प्रारम्भिक शिक्षा गांव में ही हुई। 2008 में दसवीं करने के बाद 12वीं करने में उन्हें चार वर्ष लग गए। ऐसा नहीं है कि वे पढ़ाई में कमजोर थे। 10वीं परीक्षा में मेरिट होल्डर रहे,परन्तु पारिवारिक स्थिति के चलते काम पकड़ना पड़ा। 2012 में 72 फीसदी अंकों के साथ 12वीं परीक्षा पास की।लगातार खुद की पढ़ाई के साथ-साथ अपनी दिली इच्छा की अग्नि को बुझने नहीं दिया। उनकी मेहनत की बानगी देखिए कि एक 12वीं मेडिकल का छात्र अपने समकक्ष अन्य छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता रहा,नीट कम्पीटीशन की तैयारी करवाता रहा। उसके पढ़ाए चार बच्चे डाक्टर बन गए,पर वो खुद पिछड़ता रहा। कोरोना काल में पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ी।

अब सवाल ये है कि जिसके पढ़ाये बच्चों में चार बच्चे डाक्टर बन गए, वो पीछे क्यों रहे। इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। जो वास्तव में उन छात्रों को नई राह दिखाने वाली है, जो थोड़ी सी असफलता पाकर थक हारकर बैठ जाते हैं। सार्थक परिणाम न आने पर आत्महत्या तक जैसा कदम उठा लेते हैं।

चन्दन बताते हैं कि वे शुरू से ही एंजाइटी (चिन्ता विकार) से ग्रस्त रहे। मेहनत में कोई कभी नहीं रही। परीक्षा के समय घबराहट,बेचैनी,डर, नींद न आना की स्थिति उन्हें लगातार पीछे धकेलती रही। शुरुआत में उन्होंने इस स्थिति को सामान्य माना। खुद की ही कमी मान हर बार और लग्न से तैयारी की। इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया। दो वर्ष पूर्व कुछ गुरुजनों और मित्रवरों, परिजनों ने इस बारे में साइकेट्रिक से मिलने की सलाह दी। इलाज शुरू हुआ तो मनोस्थिति और दृढ़ता की राह चल पड़ी। कोटा के प्रख्यात संस्थान ई-सरल के मेरे मेन्टर रहे उमेश सर,संजीव सर,सारांश सर और उनकी टीम ने मेरी ताकत और कमजोरी को पहचान जो रास्ता दिखाया, उसी का परिणाम है कि मैं अपने पिता के सपने को अब पूरा कर पाऊंगा।

दिल्ली में चले आन्दोलन पर उनका कहना है कि पेपर लीक होना छात्रो के लिए किसी बड़ी पीड़ा से कम नहीं है। तकलीफ बहुत होती है जब मेहनत बेकार चली जाती है। मैं तो खुद इससे प्रभावित हो चुका हूं। मेरा मानना है कि राजनीति यदि प्रभावी हो जाए तो बड़े बड़े आंदोलनों की दिशा बदल जाती है। इस्तीफों से कुछ नहीं होने वाला। भविष्य में ऐसा न हो, इस पर चिंतन हो। सजा ऐसी हो कि कोई ऐसा करने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। इतिहास गवाह है कि अस्थायी अन्याय स्थायी प्रतिभा को कभी पराजित नहीं कर सकता। चंदन कुमार की सफलता की यह कहानी यह कहती है–सपनों की उम्र नहीं होती,केवल उन्हें पूरा करने का साहस चाहिए। कठोपनिषद् की उक्ति है- उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। जिसे स्वामी विवेकानंद ने भी अपनाया था कि उठो,जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। रश्मिरथी की ये पंक्तियां चंदन साहस को और बढ़ने का कार्य करेगी -

लेकिन नौका तट छोड़ चली,
कुछ पता नहीं,किस ओर चली।
यह बीच नदी की धारा है,
सूझता न कूल-किनारा है।
ले लील भले यह धार मुझे,
लौटना नहीं स्वीकार मुझे।

प्रो.शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां...

आनंद फिल्म में लोकप्रिय फिल्म अभिनेता,राजेश खन्ना का एक डायलॉग है,, **जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहांपनाह। कौन, कैसे और कब यहां से उठ जाएगा कोई नहीं जानता।**

इससे भी पहले,मदर इंडिया,फिल्म में नरगिस ने एक गाना गया था,

दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा...

अपने आसपास की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए,मेरा नाम जोकर,फिल्म में राज कपूर ने अपने एक गाने में कहा है...

जीना यहां,मरना यहां,
इसके सिवा जाना कहां,।

मेरे द्वारा लिखे गए इन गानों का मतलब यह है कि सभी प्रकार की मजबूरियों,कठिनाईयों और शर्मिंदगियों तथा जलालत के बावजूद भी जिंदा रहने का सबक सिखाने के लिए काफी है। निराशा, असफलता,धोखाधड़ी,अपने किसी परम प्यार का हमेशा के लिए साथ छूट जाना,ऐसी बातें जीवन में होती रहती हैं,धरती पर कोई भी आदमी ऊपर लिखी गई बातों से बच नहीं सका। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारा जीना हराम कर देती हैं,कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं होता,लगता है जैसे हमें नदी में वक्त ने फेंक दिया हो,कोई रक्षक नजर नहीं आता,तैरना भी नहीं आता और किनारा भी नजर नहीं आता। ऐसे मैं हमें अपने आप को किसी न किसी तरह से बचाना तो पड़ेगा,चाहे कुछ भी करें। बहुत बार मुसीबत आने पर कोई कंधे पर हाथ नहीं रखने,सांत्वना देने वाला नहीं होता जो कहे...**मैं हूं ना...**। अगर वक्त का बादशाह समुद्र रुपी संसार में किसी मुसीबत में धक्का दे तो क्या हम मर जाएं, बिल्कुल नहीं। चाहे हमें तैरना आता हो या ना आता हो, हाथ पैर तो हमें मारने ही पड़ेंगे,अपने आप को डूबने से तो बचाना ही होगा। अगर जीवन में कोई मुसीबत आए तो उसके समाधान के लिए पहले तो खुद कोशिश करनी चाहिए,अगर खुद कामयाब ना हो सके तो किसी दूसरे शुभचिंतक से सहायता के लिए निवेदन करना चाहिए, फिर भी काम ना बने तो परमात्मा से कोई रास्ता निकालने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब परमात्मा से की गई प्रार्थना तथा अपने द्वारा हिम्मत करके उपाय करने के बावजूद भी काम ना बने तो इसे विधि का विधान समझ कर स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने इस दुनिया में रहना है जहां सब प्रकार के लोग रहते हैं। इस दुनिया में सुख देने वाले भी हैं,दुःख देने वाले भी हैं,खुशी देने वाले भी हैं, गम देने वाले भी हैं। अगर हम किसी से शिकायत करें तो काम बनने के बदले में बिगड़ सकता है। दुख के भय के मुकाबले में दुख को चुपचाप,संयम,आत्म अनुशासन,परमात्मा पर भरोसा करके सह लेना ज्यादा बेहतर है। सबको अपने-अपने हिस्से का दुख अकेले ही सहना पड़ता है। दुःख का कोई भी साझेदार नहीं होता। जब सारे वायुमंडल में प्रदूषण फैला हुआ है, हवाओं में जहर है, आप भाग कर कहां जाओगे,सांस तो इसी प्रदूषण वाली हवा में ही लेना पड़ेगा। क्या करें,मजबूरी है। इसी तरह हालात चाहे जैसे भी हों...

जीना यहां,मरना यहां,
इसके सिवा जाना कहां।

हमारे परिवार का माहौल चाहे जैसा भी हो,हमारे देश का माहौल चाहिए जैसे भी हो,सरकारी कामकाज की व्यवस्था चाहे जैसे भी हो,हमें रहना तो यही है। भाग कर हम जाएंगे कहां। बिगड़े हालात को देखकर, घबरा जाना,निराश होना,भाग जाना या आत्महत्या कर लेना,कोई समाधान नहीं। स्थिति का डटकर मुकाबला करना होगा। प्रत्येक प्रकार की पीड़ा, नाकामिया,तिरस्कार के साथ कई बार जीना पड़ता है। कहा भी गया हैं...

जो जीवन से हार गया,
उसकी हो गई छुट्टी,
मुंह चिढ़ा कर
कहे जिंदगी,
तेरी मेरी हो गई कुट्टी...।

हिम्मत बढ़ाने वाली एक और फिल्म का गाना है यह। विपरीत हालात से हार मानना कायरता कहलाता है,विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विजय का झंडा फहराना ही बहादुरी है। कुआं खोदने में काफी कठिनाई होती है लेकिन कठिन परिश्रम के बाद जो पानी निकलता है वह गंगाजल से भी ज्यादा सुख देने वाला होता है। इसी तरह जिंदगी में कठिनाइयां जितनी ज्यादा होगी उतना ही सुख भी ज्यादा मिलेगा। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय होने से प्रकाश होता है, ठीक उसी तरह मुसीबत सहने के बाद सुखदायक समय जरूर आता है। दुःख देकर तो परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है अगर हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो पुरस्कार के तौर पर ईश्वर हमें बहुत सुख देता है, बिगड़े काम बन जाते हैं,लंबी बीमारी ठीक हो जाती है,रूठे हुए लोग मान जाते हैं,खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। एक स्त्री को प्रसव पीड़ा में सामने मौत नजर आती है। लेकिन संतान उत्पन्न करने का सुख उसकी हर पीड़ा को हर लेता है। आपने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को तो देखा होगा। वह नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। जहां वह रहते हैं वहां पर ना शौचालय होता है,ना पीने का पानी,ना नालिया,ना बिजली। फिर भी यह लोग संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले लोगों से कोई इर्ष्या नहीं करते। मजदूर लोग तपती धूप में काम करते हैं,बोझ उठाते हैं, दोपहर के समय ईंटों के ऊपर सिर रखकर चैन की नींद सोते हैं जबकि अमीर आदमियों को ऐसी युक्त गद्देदार बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। गरीब लोग हैं हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। आजकल हम लोगों के पास सब कुछ है,फिर भी सुख सुख,शांति,सुकून, संतोष और बेफिक्री बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत हर प्रकार की दिक्कतों के बावजूद गरीब लोग सुख से जीते हैं। गरीब लोग रेलवे प्लेटफार्म पर सो जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं,उन्होंने मन को समझ रखा है...

जीना यहां मरना यहां,इसके सिवा जाना कहां...

या तो विपरीत हालात को ठीक किया जाए या फिर इनके साथ समझौता कर लिया जाए। जीना तो है। जिंदगी की सड़क पर धूप,छांव,कंकर,पत्थर,ऊबड़, खाबड़ तो आते रहते हैं साहब,उम्मीद के मंदिर खंडहर में तब्दील हो जाते हैं,बीमारियां भी लगती रहेगी,हमारे काम में दोष भी निकाले जाते रहेंगे,लोग हमारी टांग भी खींचते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी,जो जीता वही सिकंदर,वाली बात है। परमात्मा ने हमें यह शरीर देकर भेजा है,इसकी संभाल करना, दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना,जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना,पर हित के लिए खुद को समर्पित करना,आहार,व्यवहार में शुचिता रखना आदि बातों की तरफ ध्यान देना,जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना और जो कुछ नहीं दिया उसके लिए सब्र करना हमें आना चाहिए। हालात तो किसी भी व्यक्ति के हर समय हर प्रकार से हमेशाअनुकूल नहीं होते,औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां और बहन,जहां आरा को कैद में रखा था तो भी वह लोग मरे नहीं,जैसे कैसे जीवन व्यतीत किया,यह सब खुदा ने उनकी किस्मत में लिख रखा था भोगना ही पड़ा। हम सभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,प्रदूषण,जलवायु परिवर्तन,शहरों तथा गांवों में सफाई का अभाव तथा साधनों की कमी से पीड़ित है,फिर भी हमें जीना पड़ रहा है। किसी भी समस्या से परेशान होकर दुनिया से भाग जाना कायरता है। बस जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को यह समझाने की...

जीना यहां,मरना यहां,
इसके सिवा जाना कहां...।

जिस भी देश में जाओगे किसी न किसी प्रकार से ऐसा ही होगा। सोच ऐसी होनी चाहिए...

ना मुंह छुपा के जियो,ना सिर झुका के जियो,
गमो का दौर भी आए,मुस्कुरा के जियो।

तिरस्कार से तख्त तक :'कीड़ों' ने सत्ता नहीं,सोच को चुनौती दी

ह्यूमर का हथियार,हंगर की आग और हिम्मत की जीत अपमान से आंदोलन तक : जहाँ 'कॉकरोच' लोकतंत्र की नई भाषा बन गए...

हर युग अपने प्रतीक स्वयं गढ़ता है। कभी कोई शब्द अपमान का पर्याय होता है और कभी वही शब्द परिवर्तन का ध्वज बन जाता है। हाल के दिनों में भारतीय लोक तंत्र ने यही देखा,जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी में प्रयुक्त 'कॉकरोच'शब्द को युवाओं ने अपमान नहीं,पहचान बना लिया। देखते ही देखते वही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रतीक बन गया। जंतर-मंतर से उठी यह आवाज़ न किसी राजनीतिक दल की रैली थी,न पारंपरिक छात्र आंदोलन;यह उस पीढ़ी का सामूहिक प्रतिरोध था,जिसने वर्षों तक परीक्षाएँ दीं,लेकिन पहली बार परीक्षा लेने वाली व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए केवल पदत्याग नहीं,बल्कि उस शिक्षा तंत्र के विरुद्ध पहला सार्वजनिक अभियोग है,जिसकी जवाब देही लंबे समय से टलती रही।

प्रो.रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

विचार जब व्यंग्य का वस्त्र पहन ले, सत्ता सबसे अधिक असहज होती है। भारतीय छात्र आंदोलनों का इतिहास नारों,धरनों और टकरावों से भरा है, लेकिन सीजेपी ने प्रतिरोध की नई व्याकरण रची। जिस शब्द को अपमान माना गया,युवाओं ने उसे अपनी पहचान बना लिया। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, मनोवैज्ञानिक विजय थी। महात्मा गांधी ने जैसे नमक को साम्राज्यवादी कानून के विरुद्ध नैतिक हथियार बनाया,वैसे ही इन युवाओं ने उपहास को अपनी ताकत बना लिया। पहली बार किसी व्यंग्यात्मक नाम ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन यह साबित किया कि डिजिटल युग में प्रतीक बंदूक नहीं, बुद्धिमत्ता गढ़ती है और सम्मान दूसरों की भाषा नहीं,आत्मविश्वास से मिलता है।

हँसी कभी-कभी आँसुओं से अधिक क्रांतिकारी होती है। सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका ह्यूमर था। जहाँ पारंपरिक आंदोलनों में गुस्सा भीड़ जुटाता है,वहीं मीम्स,रील्स,व्यंग्यपूर्ण पोस्टरों और 'कीड़े' की थीम ने लाखों युवाओं को जोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई,लाठीचार्ज,बढ़ते तनाव

और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद आंदोलन ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता थी। सूचना युग में इन युवाओं ने साबित किया कि विचार केवल भाषणों से नहीं, रचनात्मक अभिव्यक्ति से भी फैलते हैं। यहाँ ह्यूमर मनोरंजन नहीं, प्रतिरोध की रणनीति था,जिसने आक्रोश को अराजकता बनने से रोका और आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाया।

भविष्य की भूख सबसे बड़ी राजनीतिक ऊर्जा होती है। सीजेपी की दूसरी ताकत उसका हंगर था–सत्ता परिवर्तन से अधिक भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की भूख। नीट पेपर लीक,बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना,परिणामों में देरी, कोचिंग माफिया का बढ़ता प्रभाव और विद्यार्थियों की आत्महत्याएँ अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि उस टूटते विश्वास के प्रमाण थीं, जिसे ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार अपनी उम्मीद,बचत और संघर्ष से वर्षों से सँजोए हुए थे। सीजेपी ने इसी मौन पीड़ा को संगठित किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस भूख की महत्वपूर्ण राज नीतिक अभिव्यक्ति है,लेकिन असली सवाल अब भी यही है–क्या केवल चेहरा बदलेगा या व्यवस्था का चरित्र भी?

नीति की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है, जिसमें प्रश्न जनता पूछती है। नीट की अवधारणा गलत नहीं थी। पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा,मेरिट आधारित चयन और पारदर्शिता उसका उद्देश्य था। लेकिन श्रेष्ठ विचार भी क्रियान्वयन पर लगातार उठते संदेहों से अविश्वसनीय हो जाते हैं। पेपर लीक,परीक्षा रद्द,तकनीकी अव्यवस्था और विलंब ने इस सुधार को संकट में बदल दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का संकेत हो सकता है, लेकिन भारतीय शिक्षा की बीमारी कहीं अधिक गहरी है। सीबीआई जाँच, दोषियों की गिरफ्तारी,परीक्षा रद्द करना और सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आवश्यक कदम हैं, पर वे लक्षणों का उपचार हैं,रोग का नहीं। असली बीमारी उस संरचना में है, जहाँ करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य एक केंद्रीकृत परीक्षा पर टिका है।

जब शिक्षा नियंत्रण का औजार बन जाए,प्रतिभा सबसे पहले घायल होती है। हमारी व्यवस्था आज भी कंट्रोल एंड कमांड मॉडल पर चल रही है। छात्र की जिज्ञासा से अधिक रैंक,और विद्यालयों की गुणवत्ता से अधिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी को महत्व मिलता है। कोचिंग उद्योग शिक्षा का पूरक नहीं, समानांतर सत्ता बन चुका है। सफलता का अर्थ सीखना नहीं, चयनित होना रह गया है। ऐसे में प्रश्न है–क्या हमारी शिक्षा छात्र-केंद्रित है या परीक्षा-केंद्रित? क्या हम ज्ञान,कौशल,अनुसंधान और सृजन शीलता विकसित कर रहे हैं,या लाखों युवाओं को एक विशाल फ़िल्टर से गुजार रहे हैं? यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल छँटनी रह जाएगा,तो प्रतिभा का विस्तार संभव नहीं होगा। सीजेपी ने यही मूल प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रख दिया है।

साहस सबसे अधिक तब चमकता है, जब उसके पीछे कोई सिंहासन न हो। जंतर-मंतर पर डटे युवाओं ने लाठीचार्ज, मुकदमे और डिजिटल ट्रोलिंग झेली,फिर भी उद्देश्य से नहीं डिगे। इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं था। अभिजीत दिपके जैसे युवा चेहरे उभरे,लेकिन नेतृत्व सामूहिक रहा। यही नई पीढ़ी का संदेश है–वह किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं करती,स्वयं मंच बनाती है। हर जनआंदोलन का खतरा यही है कि उसके शांत होते ही पुरानी व्यवस्था लौट आती है। सीजेपी ने केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि क्षतिपूर्ति,दर्ज मामलों की वापसी और व्यापक सुधारों की भी मांग की। यदि इन्हें केवल तत्कालिक शांति का उपाय माना गया, तो विफलता लौटेगी। इसलिए परीक्षा सुरक्षा में ब्लॉकचेन जैसी पारदर्शी तकनीक,कोचिंग उद्योग पर प्रभावी नियमन,विद्यालयों-महाविद्यालयों की गुणवत्ता और वैकल्पिक करियर पाथवे जैसे दीर्घकालिक सुधार अब अनिवार्य हैं।

किसी भी आंदोलन की असली जीत सत्ता नहीं,सोच बदलने में होती है। सीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाया। उसने साबित किया कि जिन्हें कभी'कीड़ा' कहकर तुच्छ समझा गया,वही बदलाव की उड़ान बन सकते हैं। यह आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं,बल्कि भविष्य की राजनीति का प्रोटोटाइप है,जहाँ भारी-भरकम संगठनों की जगह मुद्दा-आधारित,रचनात्मक नागरिक आंदोलन सत्ता से जवाब मांगेंगे। भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी फेलियर रिपोर्ट प्रश्नपत्र लीक नहीं,बल्कि वह सोच है जिसने युवाओं को प्रतियोगिता का बंदी बना दिया,सृजन का स्वामी नहीं। अब परीक्षा नीट की नहीं, नीति की है;जवाब पूरे तंत्र को देना है। यदि व्यवस्था यह संदेश समझ ले,तो'कॉकरोच'केवल प्रतीक नहीं,बल्कि ह्यूमर, हंगर और हिम्मत से बदलाव की पहचान बन जाएंगे।

भोले शब्द में शहद घुला

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर,मध्यप्रदेश

भोले भक्ति में मार ले गोते,
लूट ले मोती सारे,
मन तेरा बेकल नहीं होगा,
बह जा गंग की धारे।
भोले भक्ति में ...
भोले शब्द में शहद घुला है,
ये जीवन को तारे,
समय मिला जप ले तू भोले,
क्यूं अपने मन को मारे।
भोले भक्ति में ...
करते-करते दर्शन भोले,
अंतस मालामाल हुआ,
पंचमुखी है रूप तुम्हारा,
लगता मायाजाल हुआ।
भोले भक्ति में ...
नजर नहीं लग जाए भोले,
हमको तेरी भक्ति में,
इसीलिए जपते हैं भोले,
मिल जाएं तेरी शक्ति में।
भोले भक्ति में .....
आओ हिल मिल हम भोले का,
ऐसा रूप बखान करें,
कहीं नहीं जाएं ये भोले,
बस दिल मेरे विश्राम करें।
भोले भक्ति में ...

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

शटर खोलने में लगे ज्वेलर्स,स्कूटी से 1 करोड़ के जेवरात का बैग ले उड़े बदमाश

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात,एक आरोपी बैग लेकर पैदल भागा,आगे बाइक सवार साथी के साथ हुआ फरार; 7-8 टीमें तलाश में,50 से अधिक कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

-संवाददाता-
सीतापुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के सीतापुर मुख्य बाजार में रविवार को दिनदहाड़े करीब 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवरात से भरा बैग पार कर बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। वारदात उस समय हुई,जब ज्वेलर्स दुकान संचालक स्कूटी खड़ी कर दुकान का शटर खोल रहे थे। इसी दौरान एक युवक स्कूटी से जेवरों से भरा बैग उठाकर पैदल भाग निकला। कुछ दूरी पर उसका साथी बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। दोनों पत्थलगांव मार्ग की ओर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सीतापुर निवासी अरुण देव की सीतापुर-अंबिकापुर मार्ग पर हाईस्कूल के पास श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। वे सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन दुकान बंद होने के बाद कीमती जेवर घर ले जाते थे और सुबह दुकान खुलने से पहले साथ लेकर आते थे। रविवार सुबह करीब 11.20 बजे भी वे स्कूटी के सामने वाले हिस्से में सोने-चांदी के जेवरों से भरा बैग रखकर दुकान पहुंचे। स्कूटी खड़ी कर वे शटर खोलने लगे। कुछ ही क्षण बाद जब बैग लेने लौटे तो वह गायब था। बैग में करीब एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण होने की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

घटना की सूचना मिलते ही सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक युवक स्कूटी से बैग उठाकर पैदल जाते दिखाई दिया। कुछ दूरी पर उसका साथी बाइक के साथ खड़ा था। दोनों आरोपी बाइक से पत्थलगांव की ओर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

7-8 टीमें तलाश में, 50 से अधिक कैमरों की जांच

सीतापुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 से 8 टीमें गठित की गई हैं। सीतापुर सहित आसपास के प्रमुख मार्गों पर दबिश दी जा रही है। अब तक 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में दो आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है, हालांकि पुलिस अन्य लोगों की भूमिका से भी इनकार नहीं कर रही है।

रेकी के बाद वारदात का अंदेशा : पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी उठाइगिरी बिना पूर्व रेकी के संभव नहीं है। आशंका है कि बदमाशों ने पहले से ज्वेलर्स की दिनचर्या पर नजर रखी और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। पिछले एक-दो दिनों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला सूचीबद्ध गुंडा गिरफ्तार

पुराने लेन-देन के विवाद में युवक से मारपीट,बलरामपुर पुलिस ने आरोपी अंकित तिर्की को भेजा न्यायिक रिमांड पर

-संवाददाता-
बलरामपुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कोतवाली बलरामपुर पुलिस ने मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए सूचीबद्ध गुंडा-बदमाश अंकित तिर्की उर्फ गोलू तिर्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर युवक के साथ मारपीट करने और उसके घर में घुसकर दोबारा हमला करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार,वार्ड क्रमांक 9 पतरा पारा निवासी रोज मोहम्मद (52) ने थाना बलरामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 जुलाई 2026 को उनका पुत्र अमरजद खान ज्ञान गंगा स्कूल के पास खड़ा था। इसी दौरान मिशन रोड निवासी अंकित तिर्की उर्फ गोलू तिर्की ने पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के अनुसार,पीड़ित किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा,लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया और घर में घुसकर फिर से मारपीट की। इस घटना में पीड़ित के गले में सूजन सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 122/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3) एवं 115(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। चिकित्सकीय परीक्षण में चोटें सामान्य प्रकृति की पाई गईं। विवेचना के दौरान साक्ष्यों, गवाहों के बयान और घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 333 एवं 331(1) भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी अंकित तिर्की (34 वर्ष) को पूछताछ के लिए थाना बुलाया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 25 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार उसके परिजनों को दी गई और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी थाना बलरामपुर का सूचीबद्ध गुंडा-बदमाश है। बलरामपुर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

सरगुजा पुलिस की एक दिवसीय विवेचना कार्यशाला आयोजित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवेचकों को नए कानून ई-साक्ष्य और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के दिए गुर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक दिवसीय विवेचना कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में किया गया,जिसमें जिले के थाना एवं चौकी प्रभारी, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक तथा विवेचक शामिल हुए। कार्यशाला में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने विवेचकों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम ए सी टी),ई-साक्ष्य के उपयोग,घटना स्थल पर टेस्टिंग किट के इस्तेमाल, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साक्ष्य का आपस में तार्किक संबंध होना चाहिए तथा घटनास्थल का स्पष्ट एवं वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण गुणवत्तापूर्ण विवेचना की आधारशिला है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने केस डायरी को सीलबंद स्थिति में न्यायालय में प्रस्तुत करने,घटना स्थल का सटीक नक्शा तैयार करने, मोबाइल से फोटोग्राफी करने,जब्त सामग्री का विधिवत सील करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को केस डायरी में दर्ज करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लव रघुवंशी ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं की रात्रिकालीन गिरफ्तारी के नियम,ट्रांजिट रिमांड,पुलिस रिमांड,हथकड़ी के उपयोग, सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में निर्धारित प्रक्रिया,एससी-एसटी एक्ट,एनडीपीएस एक्ट,पशु क्रूरता अधिनियम तथा खात्मा-खारिज प्रकरणों की विवेचना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। प्रधान मजिस्ट्रेट (किशोर न्याय बोर्ड) कल्पना भगत ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि विधि से संघर्षरत बालकों के मामलों में पुलिस को सादी वर्दी में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट,मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ को सूचना देने तथा समय-सीमा के भीतर प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों, उप पुलिस अधीक्षक राकेश बघेल, एसडीओपी ग्रामीण तुल सिंह पट्टावी, डीएसपी अजाक सुरेश भगत एवं रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उपस्थित न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी विवेचकों को न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने तथा निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीबीएसई फार ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन,ओपीएस ने जीते कई पदक

चार दिन तक चला खेल महोत्सव,असम,ओडिशा,पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की टीमों ने दिखाया दम...विजेता-उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पदक देकर किया सम्मानित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

ओरिएंटल पब्लिक स्कूल (ओपीएस), अंबिकापुर में आयोजित सीबीएसई फार ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता का रविवार को रोमांचक फाइनल मुकाबलों और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ भव्य समापन हुआ। चार दिनों तक चले इस खेल महोत्सव में असम, छत्तीसगढ़,ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल,अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर निगम अंबिकापुर के सभापति हरमिंदर सिंह (टिन्नी) थे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अंबस्ट और छत्तीसगढ़ राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद इमरान अली रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक प्राचार्य डॉ. आई.ए. खान सूरी,सीबीएसई खेल पर्यवेक्षक संतोष बेहुरा, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि हरमिंदर सिंह ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ओरिएंटल पब्लिक स्कूल शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। यहां अतिथि देवो भवः की भावना का साकार रूप देखने को मिला और यहां आने वाले खिलाड़ी अंबिकापुर की मेहमाननवाजी व बेहतर आयोजन को लंबे समय तक याद रखेंगे। प्रतियोगिता में अंडर-14 बालिका वर्ग में द ग्रेट इंडिया पब्लिक स्कूल, रायपुर विजेता और ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, अंबिकापुर उपविजेता रहा। अंडर-14 बालक वर्ग में केसी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुर ने खिताब जीता, जबकि ओपीएस अंबिकापुर दूसरे स्थान पर रहा। अंडर-17 बालिका वर्ग में आर्मी पब्लिक स्कूल, गोपालपुर विजेता बना, जबकि ओपीएस चौथे स्थान पर रहा। अंडर-17 बालक वर्ग में आदर्शिला विद्या मंदिर, कोनी-बिलासपुर ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय, गोलाघाट विजेता रहा, जबकि ओरिएंटल पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालक वर्ग में केसी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुर ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान केसी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मपुर के खिलाड़ी आर्यन साहू को विषम परिस्थितियों में शानदार गोल करने के लिए विद्यालय के संस्थापक प्राचार्य डॉ. आई.ए. खान सूरी ने 1,000 का विशेष नगद पुरस्कार प्रदान किया। समापन समारोह में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। चार दिवसीय प्रतियोगिता खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए संपन्न हुई।

दोस्तों के सामने नदी में डूबा 10 साल का मासूम रातभर तलाश के बाद सुबह मिली लाश

-संवाददाता-
बिश्रामपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में घुनघुट्टा नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। बालक अपने दो दोस्तों के साथ नदी पहुंचा था, लेकिन तेज बहाव में बह गया। घटना देखकर उसके दोस्त घबरा गए और डर के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। देर शाम नदी किनारे लावारिस साइकिल और कपड़े मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली। रातभर तलाश के बाद रविवार सुबह घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर बालक का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंजनगर निवासी योगेंद्र राजवाड़े (10) शनिवार शाम करीब पांच बजे साइकिल लेकर घर से निकला था। वह अपने दो दोस्तों के साथ घूमते हुए ग्राम पंचायत हर्राटिकरा स्थित घुनघुट्टा नदी पहुंचा। यहां उसने साइकिल खड़ी कर कपड़े उतारे और नहाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण वह संभल नहीं सका और बह गया। योगेंद्र को बहता देख उसके दोनों दोस्त घबरा गए और सीधे अपने-अपने घर लौट गए। डर के कारण उन्होंने न तो अपने परिजनों को और न ही योगेंद्र के घरवालों को घटना की जानकारी दी। इससे काफी देर तक किसी को बालक के लापता होने का पता नहीं चल सका।

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो से चला सुराग

कुछ देर बाद गांव का एक युवक नदी किनारे से गुजर रहा था। उसने वहां साइकिल और कपड़े लावारिस पड़े देखे तो अनहोनी की आशंका हुई। उसने उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कर दी। फोटो वायरल होने के बाद साइकिल और कपड़ों की पहचान योगेंद्र की हुई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और जयनगर पुलिस को सूचना दी।

रातभर तलाश,सुबह मिला शव

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर रात तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इस दौरान घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर नदी में योगेंद्र का शव मिला।

पहली बारिश में ही बह गया 18 लाख का पुल,कई गांवों का संपर्क टूटा

स्कूली बच्चों,मरीजों और किसानों की बढ़ी परेशानी,ग्रामीणों ने जल्द पुनर्निर्माण व वैकल्पिक मार्ग की मांग की...

-संवाददाता-
उदयपुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

विकासखंड उदयपुर की ग्राम पंचायत पुटा में करीब 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल पहली बड़ी बारिश की परीक्षा भी पास नहीं कर सका। वर्ष 2023 में उदयपुर-चकेरी मार्ग पर बेलढाब पंडों बस्ती पहुंच मार्ग के हथफोड़ नाला पर बना पुल बारिश के तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पुल का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में ग्रामीणों की सुविधा के लिए हथफोड़ नाला पर लगभग 18 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था। लेकिन तीन वर्ष के भीतर ही तेज बारिश के दौरान पुल बह गया। इससे बेलढाब जुनपारा, पंडों बस्ती और आमाडुगू सहित आसपास के गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। पुल बहने से स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है।

ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग : ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। यदि निर्माण मानकों के अनुरूप होता तो पुल इतनी जल्दी नहीं बहता। उनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद पुल का कुछ वर्षों में बह जाना भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में तत्काल वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था की जाए, पुल का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाए तथा निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो पूरे बारिश के मौसम में क्षेत्र के ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

एनएसयूआई,8 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर...

छात्र हितों की अनदेखी का आरोप,मांगें पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

छात्र हितों से जुड़े आठ सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई ने रविवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। घड़ी चौक स्थित देव होटल के पास शुरू हुए इस आंदोलन में संगठन के पदाधिकारियों ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय और राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। एनएसयूआई का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। संगठन के जिलाध्यक्ष ज्ञान तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में लंबे समय से छात्र समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने शिक्षक भर्ती में कथित धांधली की उच्चस्तरीय जांच कराने, विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण एवं साइन बोर्ड लगाने, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की मांग की। इसके अलावा ऑनलाइन कॉपी मूल्यांकन प्रणाली समाप्त करने, जर्जर भवन में संचालित कक्षाओं को नए भवन में स्थानांतरित करने, बढ़ी हुई फीस वापस लेने, छात्रों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने तथा नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। कांग्रेस नेता द्वितेंद्र मिश्रा ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्र हितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है और सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदस्य आतिफ रजा तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उप सचिव शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने भी धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।

दैनिक घटती-घटना खबर का असर...तीन बच्चों पर तत्काल कार्रवाई,13 बच्चों की फरारी पर अब तक फैसला क्यों नहीं?

अब जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहित पूरे निगरानी तंत्र की जवाबदेही पर उठे सवाल...

तीन बच्चों के भागने पर गिरी गाज...13 अपचारी बच्चों की फरारी में जिम्मेदार कौन?

कार्रवाई का पैमाना अलग-अलग क्यों? तीन बच्चों पर निलंबन,13 बच्चों पर इंतजार!

अधीक्षक निलंबित...अब जिला बाल संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी पर भी सवाल

जब तीन बच्चों पर हुई कार्रवाई,तो 13 अपचारी बच्चों की फरारी में जवाबदेही कौन तय करेगा?

बार-बार फरारी, अब निलंबन...लेकिन 13 बच्चों की फरारी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

क्या केवल अधीक्षक ही जिम्मेदार? अब पूरे बाल संरक्षण तंत्र पर उठे सवाल

तीन बच्चों के भागने पर अधीक्षक निलंबित...13 अपचारी बच्चों की फरारी में किसे बचाया जा रहा है?

तीन बच्चों की फरारी पर अधीक्षक निलंबित...फिर 13 अपचारी बच्चों की फरारी पर कार्रवाई क्यों नहीं?

क्या केवल अधीक्षक ही जिम्मेदार, या जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहित पूरे निगरानी तंत्र की भी तय होगी जवाबदेही?

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले की बाल संरक्षण व्यवस्था पिछले छह महीनों से लगातार सवालों के घेरे में है,अपचारी बच्चों के एक के बाद एक फरार होने की घटनाओं ने केवल सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर नहीं किया,बल्कि प्रशासनिक निगरानी, विभागीय जवाबदेही और बाल संरक्षण तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। इन घटनाओं को लेकर दैनिक घटती-घटना ने फरवरी 2026 से लगातार समाचार प्रकाशित किए,सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया और हर बार यह सवाल उठाया कि आखिर बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है,अब उन खबरों के बाद प्रशासन ने प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) अंबिकापुर के प्रभारी अधीक्षक को निलंबित कर दिया है,कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संस्थान से बार-बार बच्चों के भागने की घटनाएं हो रही थीं तथा सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर प्रभारी अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा अन्य अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया,

निलंबन की यह कार्रवाई निश्चित रूप से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही एक नया और बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, यदि तीन बच्चों की फरारी पर तत्काल अधीक्षक को निलंबित किया जा सकता है, तो 14 जुलाई को बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बच्चों के फरार होने की घटना में अब तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

बता दे की प्लेस ऑफ सेफ्टी के प्रभारी अधीक्षक का निलंबन यह दर्शाता है कि प्रशासन ने हालिया घटना को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा संबंधी निर्देशों के पालन में कमी को कार्रवाई का आधार माना है, साथ ही, इससे पहले हुई 13 अपचारी बच्चों की फरारी जैसी बड़ी घटना में जवाबदेही तय होने की स्थिति को लेकर उठ रहे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं,इनका उत्तर संबंधित जांच,उपलब्ध तथ्यों और प्रशासनिक निर्णयों से ही स्पष्ट होगा,छह महीनों में चार फरारी की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यकता केवल एक निलंबन की नहीं, बल्कि पूरे बाल संरक्षण तंत्र की निष्पक्ष समीक्षा,सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण,निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। तभी यह भरोसा कायम हो सकेगा कि सुधार गृह वास्तव में सुधार और सुरक्षा के केंद्र बनेंगे,न कि बार-बार फरारी की घटनाओं के कारण चर्चा में आने वाले संस्थान।

चार घटनाओं ने हिला दी पूरी व्यवस्था-

वर्ष 2026 में सरगुजा के बाल संरक्षण संस्थानों में फरारी की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं, सबसे पहले 17 फरवरी को प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बच्चे फरार हुए। यह घटना प्रदेशभर में चर्चा का विषय बनी। उस समय सुरक्षा व्यवस्था, क्षमता, निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठे, इसके बाद 24 जून को बाल संप्रेक्षण गृह से 11 बच्चे फरार हो गए। माना गया कि पहली घटना से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी, लेकिन 14 जुलाई को फिर बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बच्चे भाग गए, लगातार दूसरी बार एक ही संस्था से बड़ी संख्या में बच्चों के फरार होने की घटना ने स्पष्ट संकेत दिया कि सुधारात्मक कदम अपेक्षित स्तर तक प्रभावी नहीं रहे, इसके बाद 23 जुलाई की रात प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए, यह घटना इसलिए और अधिक गंभीर मानी गई क्योंकि उसी दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई थी, इन चार घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि समस्या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है, प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह दोनों से दो-दो बार बच्चे फरार हो चुके हैं। यानी पूरे बाल संरक्षण तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था कठघरे में खड़ी है।

दैनिक घटती-घटना लगातार उठाता रहा सवाल-

इन घटनाओं के दौरान दैनिक घटती-घटना ने केवल समाचार प्रकाशित नहीं किए, बल्कि हर घटना के बाद उससे जुड़े प्रशासनिक पहलुओं को भी सामने रखा, अखबार ने सवाल उठाया कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहां है? बार-बार बच्चे क्यों भाग रहे हैं? क्या सुरक्षा ऑडिट हुआ? क्या निरीक्षण रिपोर्टों पर अमल हुआ? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई? क्या वर्षों से चली आ रही व्यवस्थागत कमियों को दूर किया गया? फरवरी की पहली घटना से लेकर जुलाई की चौथी घटना तक लगातार प्रकाशित खबरों ने इस पूरे मामले को जनचर्चा का विषय बनाए रखा। अब अधीक्षक के निलंबन के बाद यह माना जा रहा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है।

आदेश में क्या कहा गया है?-कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में बार-बार बच्चों के भागने की घटनाएं हो रही थीं,संस्थान की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए निर्देश दिए गए थे,उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप प्रभारी अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, यानी आदेश का आधार केवल एक घटना नहीं, बल्कि बार-बार हो रही घटनाएं और सुरक्षा निर्देशों का पालन न होना बताया गया है।

यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल-यदि निलंबन का आधार 'बार-बार बच्चों का भागना' और 'सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं होना' है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यही कसौटी 13 बच्चों की फरारी वाली घटना पर क्यों लागू नहीं हुई? 14 जुलाई को 13 अपचारी बच्चों के फरार होने की घटना संख्या और गंभीरता दोनों दृष्टियों से बड़ी घटना थी,यदि उस समय भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी,तो क्या जिम्मेदारी तय हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों? और यदि जांच अभी भी जारी है, तो उसमें इतना समय क्यों लग रहा है?

क्या कार्रवाई के अलग-अलग मानक हैं?- अब प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि समान प्रकृति की घटनाओं में अलग-अलग प्रकार की कार्रवाई क्यों दिखाई दे रही है,यदि तीन बच्चों की फरारी पर तत्काल निलंबन संभव है,तो 13 बच्चों की फरारी के मामले में क्या परिस्थितियां अलग थीं? क्या जांच रिपोर्टों में अलग निष्कर्ष आए? क्या किसी स्तर पर लापरवाही सिद्ध नहीं हुई? इन प्रश्नों का उत्तर प्रशासनिक पारदर्शिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या केवल अधीक्षक ही जिम्मेदार हैं?-पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ रहा है, क्या किसी भी बाल संरक्षण संस्था में होने वाली सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी केवल अधीक्षक की होती है? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संस्था का संचालन बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत होता है,संस्थान स्तर पर अधीक्षक होते हैं, जिला स्तर पर निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था होती है,विभागीय अधिकारी समय-समय पर समीक्षा करते हैं, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाती है, ऐसे में यदि सुरक्षा व्यवस्था बार-बार विफल हो रही है, तो यह देखना भी आवश्यक है कि निगरानी तंत्र कितना प्रभावी था।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी की भूमिका भी चर्चा में-इसी कारण अब जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं,यदि नियमित निरीक्षण किए गए थे तो क्या सुरक्षा संबंधी कमियां चिन्हित की गई थीं? यदि की गई थीं तो उन्हें दूर कराने के लिए क्या कार्रवाई हुई? क्या अधीक्षक को लिखित निर्देश दिए गए? क्या निर्देशों के पालन की समीक्षा हुई? यदि पालन नहीं हुआ तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि निरीक्षण में कोई कमी नहीं मिली थी,तो फिर चार बार फरारी की घटनाएं कैसे हो गईं? इन प्रश्नों का उत्तर पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

2012 से रिक्त पद का मुद्दा भी फिर चर्चा में-

इस पूरे मामले के बीच यह मुद्दा भी बार-बार सामने आता रहा है कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी का नियमित पद वर्ष 2012 से रिक्त होने और लंबे समय से प्रभारी व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन होने की बात कही जाती रही है, यदि वास्तव में ऐसा है,तो यह भी प्रशासनिक समीक्षा का विषय बनता है कि क्या नियमित नेतृत्व के अभाव का असर निगरानी व्यवस्था पर पड़ा, यह पहलू भी व्यापक जांच का हिस्सा बन सकता है।

बैठकें हुई,निर्देश दिए गए, फिर भी नहीं रुकी घटनाएं...

हर घटना के बाद विभागीय बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए,निरीक्षण किए गए,जांच समितियां बनीं, लेकिन कुछ समय बाद फिर बच्चे फरार हो गए,23 जुलाई को तो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई और उसी रात तीन बच्चे भाग गए,यह घटनाक्रम बताता है कि केवल बैठकें और निर्देश पर्याप्त नहीं हैं। जब तक उनका प्रभावी पालन नहीं होगा,तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना कठिन होगा।

क्या पूरे तंत्र की होगी समीक्षा?-

अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एक अधिकारी पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरे तंत्र की निष्पक्ष समीक्षा हो,विशेषज्ञ मानते हैं कि निम्न बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है सभी फरारी की घटनाओं की जांच रिपोर्टों की समीक्षा, सुरक्षा ऑडिट,संस्थानों की संरचनात्मक सुरक्षा का मूल्यांकन,निरीक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता की जांच, जिम्मेदारी तय करने के समान मानक, रिक्त पदों की पूर्ति, नियमित निगरानी और अनुपालन की व्यवस्था।

जनता पूछ रही है...

- तीन बच्चों के भागने पर अधीक्षक निलंबित हुए,तो 13 बच्चों की फरारी पर कार्रवाई क्यों नहीं?
- क्या जिला बाल संरक्षण अधिकारी की प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होगी?
- क्या निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी?
- क्या सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन वास्तव में हुआ था?
- क्या पूरे बाल संरक्षण तंत्र का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?
- क्या सभी मामलों में समान मानकों पर कार्रवाई होगी?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर राजपुर में कांग्रेस का विजय मार्च,पटाखे फोड़कर मनाया जश्न

-संवाददाता-

राजपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के राजपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय मार्च निकालकर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से गांधी चौक तक रैली निकाली तथा पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। विजय मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल एक मंत्री के

इस्तीफे का मामला नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों, युवाओं और जनआवाज की जीत का प्रतीक है। उन्होंने इसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संघर्ष और छात्र आंदोलन की सफलता बताया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संघर्ष के माध्यम से जनता की आवाज को मजबूती मिली है। नेताओं ने इसे सत्य, संघर्ष और जनशक्ति की विजय करार दिया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिहर यादव, सामरी के पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम,जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी,युवा कांग्रेस, सेवा दल,एनएसयूआई तथा कांग्रेस परिवार के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पंचायत विकास निधि में लाखों की कथित अनियमितता,जिम्मेदार कौन?

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने सरपंच,सचिव और उपसरपंच पर लगाए शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप,सीईओ जिला पंचायत व एसडीएम से जांच की मांग

सुदामा राजवाड़े

राजपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लाऊ में पंचायत विकास निधि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के जिला सचिव उमेश सिंह ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा राजपुर एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपकर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं उपसरपंच पर शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। 24 जुलाई 2026 को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर राशि का आहरण तो कर लिया गया,लेकिन संबंधित कार्य धरातल पर नहीं हुए। शिकायत के अनुसार नवंबर 2025 में उपसरपंच के घर से सेवारी सीमा तक मुरमीकरण कार्य कराया जाना था। आरोप है कि यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि इसके नाम पर 1 लाख का आहरण कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने इसे फर्जी भुगतान बताते हुए जांच की मांग की है। शिकायत में एक अन्य गंभीर आरोप वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शाला धमधिया पारा की बाउंड्रीवाल निर्माण से जुड़ा है। बताया गया है कि

शिक्षा अनुदान मद से 10 लाख की स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। आरोप है कि मौके पर केवल गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए, जबकि 5 लाख का भुगतान कर लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भी वित्तीय अनियमितता का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने मांग की है कि पंचायत निधि के उपयोग की विस्तृत जांच कराई जाए, दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। संस्था का कहना है कि पंचायत निधि जनता के विकास के लिए होती है और उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल शिकायत जिला पंचायत और प्रशासन के पास पहुंच चुकी है।

अब यह देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों की कितनी गंभीरता से जांच करता है और क्या पंचायत विकास निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का बयान सामने आना शेष है।

हेलमेट छूटा,कुछ देर बाद हादसा...नशेड़ी बाइक सवार की टक्कर से स्कूल संचालक की मौत

पेट्रोल पंप उद्घाटन समारोह से लौटते समय हुआ हादसा, रामानुजनगर अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम

-संवाददाता-

रामानुजनगर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। रामानुजनगर के समीप ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सडक़ हादसे में निजी स्कूल संचालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा से तेज और लापरवाही से आ रहे कथित नशेड़ी बाइक सवार ने उनकी बुलेट को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने से घायल स्कूल संचालक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम जमड़ी, भैयाथान निवासी सत्यप्रकाश दुबे (49) रविवार को रामानुजनगर में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। समारोह के बाद वे अपने एक रिश्तेदार से मिलने ग्राम केशवपुर जा रहे थे। इसी दौरान रामानुजनगर से लगे ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर में सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बुलेट में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सत्यप्रकाश दुबे सडक़ पर सिर के बल जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है तथा दुर्घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। परिजनों और परिचितों के अनुसार सत्यप्रकाश दुबे हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाते थे। वे भैयाथान से हेलमेट पहनकर ही रामानुजनगर आए थे, लेकिन पेट्रोल पंप उद्घाटन समारोह के दौरान उनका हेलमेट वहीं छूट गया। इसके बाद वे बिना हेलमेट के ही रिश्तेदार के घर के लिए निकल पड़े। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी जान चली गई। सत्यप्रकाश दुबे भारद्वाज पब्लिक स्कूल के संचालक थे। उनके आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।

जंगल असुरक्षित, निर्माण विवादित...कोरिया वन मंडल में आखिर जवाबदेही किसकी?

चंदन गया, तालाब बहा... अब जवाबदेही भी जंगल में खो गई क्या?

कोरिया वन मंडल में संरक्षण नहीं, भ्रष्टाचार का 'संरक्षण'! आखिर किसके साए में चल रही अनियमितताएं?

वन विभाग या निर्माण विभाग? जंगल बचाने से ज्यादा निर्माणों में क्यों उलझा कोरिया वन मंडल

चंदन चोरी से लेकर बहते तालाब तक... हर कांड पर चुप्पी,आखिर किसे बचा रहा वन विभाग?

जंगल में जो चाहे करो! कोरिया वन मंडल में शिकायतें भी बेअसर, कार्रवाई भी नदारद...

तालाब बहा,चंदन गायब...लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?

कोरिया वन मंडल में एक के बाद एक अनियमितताओं पर सवाल, फिर भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं

कोरिया वन मंडल में संरक्षण नहीं, 'निर्माण और मौन' का राज? बार-बार उजागर हो रही अनियमितताओं पर आखिर जिम्मेदार कौन?

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। वन विभाग का नाम आते ही सबसे पहले जंगल, वन्यजीव, पौधों का संरक्षण,अवैध कटाई पर रोक और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की तस्वीर सामने आती है,लेकिन कोरिया वन मंडल की तस्वीर कुछ अलग कहानी कहती नजर आ रही है,यहां ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जंगलों की हरियाली से ज्यादा रुचि निर्माण कार्यों में दिखाई दे रही है और संरक्षण से ज्यादा 'संरक्षण' उन लोगों को मिल रहा है जिन पर सवाल उठ रहे हैं,दैनिक घटती-घटना लगातार वन विभाग से जुड़े मामलों को उजागर करता रहा है,कभी सरकारी नर्सरी से लाखों रुपये मूल्य के चंदन के पेड़ गायब होने का मामला सामने आया, कभी तालाब निर्माण में मशीनों के उपयोग और गुणवत्ता पर सवाल उठे, फिर पहली ही बारिश में तालाब बह गया, लेकिन इन घटनाओं के बाद यदि कुछ नहीं बदला तो वह है, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था, ऐसा लगने लगा है कि कोरिया वन मंडल में यदि कोई अनियमितता होती है तो सबसे पहले उसकी जांच की बात होती है,फिर फाइल बनती है, फिर समय गुजरता है और अंत में मामला भी जंगल की हरियाली में कहीं गुम हो जाता है।

चंदन गया... लेकिन जिम्मेदार नहीं मिले- सरकारी नर्सरी,जहां सबसे सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए,वहीं से बहुमूल्य चंदन के पेड़ गायब हो गए, सवाल उठे कि आखिर पेड़ हवा में उड़ गए या जमीन निगल गई? लेकिन जनता आज भी उसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर इस पूरे मामले में किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई? यदि मुख्यालय की नर्सरी ही सुरक्षित नहीं रह सकी तो दूरस्थ जंगलों की सुरक्षा के दावे कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है।

तालाब बना...पहली बारिश आई...और सच्चाई बहकर बाहर आ गई-

इसके बाद सोनहत क्षेत्र में जल संरक्षण के नाम पर तालाब निर्माण का मामला सामने आया, निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने शुरुआत से ही गुणवत्ता पर सवाल उठाए, दैनिक घटती-घटना ने इन सवालों को प्रमुखता से प्रकाशित किया, फिर पहली तेज बारिश हुई और तालाब का एक हिस्सा बह गया, यह केवल मिट्टी का कटाव नहीं था, इसके साथ निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल भी मजबूत हो गए, यदि निर्माण मानकों के अनुरूप हुआ था तो पहली ही बारिश में वह क्यों बह गया? यदि गुणवत्ता सही थी तो तकनीकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई? यदि गुणवत्ता गलत थी तो भुगतान कैसे हो गया? इन सवालों का उत्तर आज भी जनता को नहीं मिला।

क्या वन विभाग का मूल काम बदल गया है?-

वन विभाग का मूल उद्देश्य जंगल बचाना, वन्यजीवों की सुरक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन हाल के वर्षों में जो मामले सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा निर्माण कार्यों की हो रही है, कहीं तालाब...कहीं सड़क...कहीं मिट्टी...कहीं मशीन...कहीं गुणवत्ता...ऐसा लगने लगा है कि जंगलों की रक्षा अब दूसरे नंबर पर है और निर्माण गतिविधियां पहले नंबर पर।

जंगल में जो चाहे करो...कोई पूछने वाला नहीं?- ग्रामीणों का कहना है कि जिस विभाग को अवैध कटाई रोकनी चाहिए, उसी विभाग के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, यदि जंगल के बीच करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य हों और उन पर गुणवत्ता के गंभीर आरोप लगें...यदि पहली ही बारिश में निर्माण बह जाए...यदि सरकारी नर्सरी से चंदन के पेड़ गायब हो जाएं...यदि सूचना बोर्ड तक न लगाए जाएं...और फिर भी किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय न हो...तो जनता आखिर क्या निष्कर्ष निकाले?

हर खबर के बाद वही कहानी— जांच होगी... कार्रवाई होगी... फिर सन्नाटा- कोरिया वन मंडल में यह एक नई परंपरा बनती दिखाई दे रही है,पहले घटना, फिर शिकायत,फिर खबर,फिर जांच का आश्वासन, फिर कुछ दिन चर्चा, और उसके बाद...मौन,जनता पूछ रही है कि क्या जांच केवल इसलिए होती है ताकि कार्रवाई न करनी पड़े?

क्या अधिकारियों का संरक्षण ही सबसे बड़ा संरक्षण है?-अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी शिकायतों के बाद भी यदि जिम्मेदारी तय नहीं होती तो इसका कारण क्या है? क्या निगरानी कमजोर है? क्या व्यवस्था कमजोर है? या फिर जिन पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें विभागीय संरक्षण प्राप्त है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद भी किसी बड़े अधिकारी की जवाबदेही सार्वजनिक रूप से तय होती दिखाई नहीं देती।

डीएफओ की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल- वन मंडल का प्रशासनिक और कार्यकारी नेतृत्व संभालने वाले अधिकारी के रूप में स्वाभाविक रूप से लोगों की नजर जिला वन अधिकारी (छ्स्नह) पर भी जाती है, जनता पूछ रही है–क्या इतनी सारी घटनाएं उनकी जानकारी के बिना हो रही हैं? यदि जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल क्यों न उठें? और यदि शिकायतें लगातार मिल रही थीं तो सुधारात्मक कदम क्यों दिखाई नहीं दिए? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है।

सरकारी पैसा... लेकिन जवाबदेही निजी क्यों हो जाती है?-सरकारी योजनाओं का पैसा जनता का पैसा है, तालाब भी जनता का, जंगल भी जनता का, चंदन भी जनता का, लेकिन जब नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसी की नहीं रहती, क्या सरकारी धन केवल खर्च दिखाने के लिए है? क्या गुणवत्ता केवल कागजों में होती है? क्या निरीक्षण केवल फाइलों तक सीमित रह गया है?

दैनिक घटती-घटना लगातार उठाता रहा सवाल...

दैनिक घटती-घटना ने क्रमबद्ध तरीके से इन मामलों को सामने रखा सरकारी नर्सरी से चंदन चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, तालाब निर्माण में मशीनों और गुणवत्ता पर सवाल, पहली बारिश में तालाब बहने की खबर, निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी परीक्षण की मांग, विभागीय जवाबदेही पर लगातार सवाल, लेकिन इन खबरों के बाद भी यदि व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो यह स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंतन का विषय है।

अब जनता केवल जांच नहीं,परिणाम चाहती है...

लोगों का कहना है कि हर बार जांच समिति बना देना पर्याप्त नहीं है, यदि कहीं भी गुणवत्ता में कमी,वित्तीय अनियमितता,तकनीकी लापरवाही या नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए,सबसे बड़ा सवाल तालाब तो बह गया...चंदन के पेड़ भी कट गए...लेकिन क्या हर बार जिम्मेदारी भी बह जाएगी? या फिर इस बार कोरिया वन मंडल में केवल निर्माण नहीं, जवाबदेही की भी नींव रखी जाएगी?

तिरंगा यात्रा के लिए भाजपा ने जिला व मंडल स्तरीय टोलियों की घोषणा की

जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले ने जारी किया आदेश,सभी मंडलों में राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली देशव्यापी तिरंगा यात्रा के सफल संचालन के लिए भाजपा जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) ने जिला एवं मंडल स्तरीय टोलियों की घोषणा कर दी है, इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती चंपा देवी पावले ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आदेश के अनुसार सुशील सिंह को जिला टोली का संयोजक बनाया गया है, वहीं प्रतिमा पटवा, अभय जायसवाल एवं अंकित शर्मा को जिला टोली का सदस्य नियुक्त किया गया है।

मंडलों में भी घोषित हुई जिम्मेदारियां- भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार चिरमिरी मंडल में धर्मेन्द्र त्रिपाठी को संयोजक तथा मालती काशीपुरी एवं आकाश दास को सदस्य बनाया गया है, मनेन्द्रगढ़ मंडल में जयंती यादव को संयोजक, जबकि अंजना विश्वकर्मा एवं राहुल जायसवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है,खड़गवां मंडल में रमेश जायसवाल संयोजक होंगे,उनके साथ मालती यादव एवं सत्येन्द्र साहू सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, हसदेव मंडल में भगवान दास को संयोजक तथा रेनु सिंह एवं अनिल सिंह को सदस्य बनाया गया है, नागपुर मंडल में अमित राय को संयोजक तथा कन्याकुमारी एवं नीलकमल राउत को सदस्य नियुक्त किया गया है,केल्हारी मंडल में शरद कौशिक को

संयोजक,जबकि श्रीमती किरण एवं दलबीर चक्रधारी को सदस्य बनाया गया है, कुवांरपुर मंडल में भैया प्रसाद को संयोजक तथा श्रीमती नंदनी गुप्ता एवं चन्द्रप्रताप मूर्तिया को सदस्य बनाया गया है, जनकपुर मंडल में मणिप्रसाद पाण्डेय को संयोजक तथा प्रीति साहू एवं शुभम सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है, इसी प्रकार कोटाडोल मंडल में श्रीचंद यादव को संयोजक तथा श्रीमती गीता सिंह एवं इन्द्रभान यादव को सदस्य बनाया गया है।

अधिक से अधिक जनभागीदारी पर रहेगा जोर-भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले ने कहा कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार गठित यह टोली जिले के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी निभाएगी,उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, उन्होंने सभी नवनियुक्त संयोजकों एवं सदस्यों से संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया।

आयुष चिकित्सकों के हक की बुलंद आवाज,डॉ. भुवन भास्कर साहू ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

संविदा पद बढ़ाने और 2022 से लंबित नियमित भर्ती शुरू करने की मांग, कहा-आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नियुक्तियां जरूरी

संवाददाता

कोरिया/रायपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में आयुष चिकित्सकों की लंबित मांगों और रोजगार के अवसरों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिला कोरिया के संयोजक डॉ. भुवन भास्कर साहू ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के संविदा पदों की संख्या बढ़ाने और वर्ष 2022 से लंबित नियमित भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है, ज्ञापन में डॉ. साहू ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जारी संविदा भर्ती विज्ञापन में पूरे प्रदेश के लिए केवल 48 पद स्वीकृत किए गए हैं, जबकि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और योग्य आयुष चिकित्सक रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं,ऐसे में सीमित पदों के कारण अधिकांश अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पा रहा है और युवाओं में निराशा का वातावरण बन रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त पद जरूरी- डॉ. भुवन भास्कर साहू ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, यदि पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है तो आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा

सकती हैं,उन्होंने कहा कि वर्तमान में पदों की संख्या आवश्यकता की तुलना में काफी कम है, जिससे आयुष सेवाओं के विस्तार की गति प्रभावित हो रही है,उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केवल संविदा भर्ती तक सीमित नहीं रहना चाहिए,बल्कि लंबे समय से लंबित नियमित भर्ती प्रक्रिया को भी तत्काल प्रारंभ करना चाहिए,ताकि योग्य चिकित्सकों को स्थायी अवसर मिल सकें और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिले।

2022 से लंबित नियमित भर्ती जल्द शुरू करने की मांग- ज्ञापन में प्रमुख रूप से तीन मांगें रखी गई हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जारी संविदा भर्ती में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पदों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाए,वर्ष 2022 से लंबित नियमित भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ किया जाए, योग्य एवं अनुभवी आयुष चिकित्सकों को जनसेवा का अवसर देकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए।

प्रधानमंत्री के विजन का किया उल्लेख- डॉ. साहू ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद, योग एवं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यदि राज्य स्तर पर पर्याप्त संख्या में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होगी, तो इस लक्ष्य को प्रभावी रूप से पूरा करना कठिन होगा, उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र केवल उपचार का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, जीवनशैली और स्वास्थ्य संरक्षण की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार को पर्याप्त पद सृजित कर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करनी चाहिए।

आयुष चिकित्सकों में जगी उम्मीद- डॉ. भुवन भास्कर साहू की इस पहल के बाद प्रदेश के आयुष चिकित्सकों और भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लंबे समय से नियमित भर्ती और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे चिकित्सकों का मानना है कि यदि शासन इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेता है तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत होगी, आयुष चिकित्सकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों की सेवाओं की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, ऐसे में रिक्त पदों को भरना और नई नियुक्तियां करना समय की मांग है।

आयुष चिकित्सकों का सम्मान और भविष्य हमारी प्राथमिकता- ज्ञापन सौंपने के बाद डॉ. भुवन भास्कर साहू ने कहा आयुष चिकित्सकों का सम्मान और उनका भविष्य हमारी प्राथमिकता है, योग्य चिकित्सकों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, जब तक आयुष चिकित्सकों के हितों की रक्षा और नियमित भर्ती सुनिश्चित नहीं होती, तब तक हमारी मांग शासन के समक्ष मजबूती से उठती रहेगी, उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे,जिससे प्रदेश के आयुष चिकित्सकों को न्याय मिल सके और आम जनता को बेहतर आयुष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

कोरिया कलेक्टरेट का 'फेविकोल मॉडल'! क्या स्टेनो टू कलेक्टर का पद अब आजीवन प्रतिनियुक्ति का पर्याय बन गया है?

कई खुलासे...फिर भी शासन मौन! खबरें गलत थीं तो खंडन क्यों नहीं? सही थीं तो कार्रवाई क्यों नहीं?

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी नियमों की किताबें अक्सर धूल खाती रहती हैं,लेकिन जब कोई फाइल वर्षों तक बिना हिले-डुले एक ही टेबल पर टिकी रह जाए,तो लोग मजाक में कहते है...यह फाइल नहीं,सरकारी विरासत है।'कोरिया कलेक्टरेट में स्टेनो टू कलेक्टर का मामला भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है,फर्क सिर्फ इतना है कि यहां फाइल ही नहीं, प्रतिनियुक्ति भी मानो स्थायी विरासत बन गई हो।

दैनिक घटती-घटना पिछले कई सप्ताह से इस पूरे प्रकरण पर लगातार दस्तावेजों के आधार पर समाचार प्रकाशित कर रहा है, प्रतिनियुक्ति के आदेश,सेवा पुस्तिका, मत्स्य महासंघ के पत्र,राजस्व विभाग में कार्य, वेतन निर्धारण,सेवा निरंतरता और संविलियन के प्रयास जैसे कई पहलू सामने आ चुके हैं,लेकिन जितने दस्तावेज सामने आए,उससे कहीं अधिक गहरी होती चली गई शासन-प्रशासन की चुप्पी,अब सवाल केवल एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली का बन गया है।

12 खबरें,दर्जनों दस्तावेज...फिर भी चुप्पी! आखिर शासन क्या संदेश देना चाहता है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी समाचार पत्र द्वारा किसी मामले पर एक-दो नहीं बल्कि लगातार 12 बार दस्तावेजों के साथ समाचार प्रकाशित किए जाएं, गंभीर प्रशासनिक सवाल उठाए जाएं और उसके बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से न कोई आधिकारिक खंडन आए, न कोई तथ्यात्मक स्पष्टीकरण और न ही किसी जांच की सार्वजनिक जानकारी मिले, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठना लाजिमी है,यदि प्रकाशित खबरें गलत थीं, तो सबसे पहले संबंधित विभाग का दायित्व था कि वह रिकॉर्ड के साथ उनका खंडन करता,तथ्यों को सार्वजनिक करता और भ्रम दूर करता,लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ,तो दूसरी ओर यह भी जरूरी नहीं कि केवल चुप्पी को खबरों की पुष्टि मान लिया जाए,फिर भी लगातार बनी रहने वाली यह चुप्पी स्वयं एक सार्वजनिक प्रश्न बन जाती है,अब लोग पूछने लगे हैं कि आखिर शासन इस चुप्पी से क्या संदेश देना चाहता है? क्या यह संदेश पारदर्शिता का है, या फिर यह संकेत देता है कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या शासन यह बताना चाहता है कि दस्तावेजों के साथ उठाए गए सवाल भी प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हैं? या फिर यह चुप्पी अनजाने में ऐसी धारणा को जन्म दे रही है कि प्रभावशाली लोगों के मामलों में जवाबदेही की अपेक्षा कम हो जाती है? शासन की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शिता,जवाबदेही और समय पर प्रतिक्रिया होती है,जब गंभीर सवालों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आता,तब खाली स्थान को अफवाहें,चर्चाएं और अटकलें भरने लगती हैं, यही कारण है कि अब प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी सुनाई देने लगी है कि 'क्या यह चुप्पी किसी संरक्षण का संकेत मानी जाए, या केवल प्रशासनिक उदासीनता?' इन चर्चाओं का उत्तर केवल एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक प्रशासनिक प्रतिक्रिया ही दे सकती है,क्योंकि लोकतंत्र में सवालों को अनदेखा करने से वे समाप्त नहीं होते, बल्कि समय के साथ और बड़े होते जाते हैं,यदि शासन के पास इस पूरे मामले का स्पष्ट और नियमसम्मत उत्तर है,तो उसे सार्वजनिक करना सबसे प्रभावी तरीका होगा,इससे न केवल भ्रम दूर होगा,बल्कि शासन की विश्वसनीयता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।

प्रतिनियुक्ति या स्थायी नियुक्ति? नियमों की किताब पूछ रही है...

मुझे पढ़ा भी गया था या नहीं?...सरकारी सेवा नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था होती है,किसी विभाग में तत्काल आवश्यकता होने पर दूसरे विभाग के कर्मचारी की सेवाएं सीमित अवधि के लिए ली जाती हैं,सामान्यतः यह अवधि तीन वर्ष और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम पांच वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन कोरिया में चर्चा किसी तीन या पांच वर्ष की नहीं,बल्कि लगभग 24 वर्षों की है, यहीं से व्यंग्य जन्म लेता है,लोग पूछ रहे हैं–क्या कोरिया जिले में प्रतिनियुक्ति का नया संस्करण लागू हो चुका है,जिसमें 'अस्थायी' का अर्थ 'आजीवन' हो गया है?

मत्स्य विभाग का कर्मचारी...लेकिन राजस्व विभाग की पहचान

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संबंधित कर्मचारी मूल रूप से मत्स्य महासंघ से संबद्ध रहे,राज्य पुनर्गठन के बाद उन्हें मत्स्य महासंघ में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी आदेश भी जारी हुए,बाद के वर्षों में वे कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत रहे और स्टेनो टू कलेक्टर के रूप में पहचान बनती गई,यहीं सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रश्न उठता है यदि मूल विभाग मत्स्य था, तो राजस्व विभाग में इतनी लंबी अवधि तक कार्य किस नियम के अंतर्गत जारी रहा? यदि संविलियन हुआ था तो उसका स्पष्ट आदेश कहां है? यदि संविलियन नहीं हुआ,तो प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं हुई?

कलेक्टर बदलते रहे...लेकिन कुर्सी ने शायद कैलेंडर देखना छोड़ दिया- कोरिया जिले में वर्षों के दौरान अनेक कलेक्टर आए और गए। शासन बदला,सरकारें बदलीं,प्रशासनिक प्राथमिकताएं बदलीं,लेकिन इस व्यवस्था को देखकर कर्मचारी अब व्यंग्य में कहते हैं–'कलेक्टर का तबादला सरकारी प्रक्रिया है,लेकिन स्टेनो की कुर्सी शायद प्राकृतिक धरोहर घोषित हो चुकी है,' यह टिप्पणी तथ्य नहीं,बल्कि प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चा का व्यंग्य है, लेकिन ऐसी चर्चाएं तब जन्म लेती हैं, जब लंबे समय तक किसी व्यवस्था पर सवाल उठें और उनका स्पष्ट उत्तर सामने न आए।

कार्य विभाजन में सबका नाम...लेकिन इस व्यवस्था पर सन्नाटा- हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में कार्य विभाजन के आदेश जारी हुए, विभिन्न शाखाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई,लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रश्नों पर कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया,अब कर्मचारी पूछ रहे हैं क्या यह विषय इतना संवेदनशील है कि उस पर बोलना भी वर्जित हो गया?

वेतन का सवाल—निर्धारण किसने किया?- पूरे प्रकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू वेतन है, यदि उपलब्ध जानकारी सही है और संबंधित कर्मचारी को लगभग 1.46 लाख प्रतिमाह वेतन-भत्ते मिल रहे हैं, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वेतन निर्धारण किस नियम से हुआ? मूल विभाग ने किया या राजस्व विभाग ने? वार्षिक वेतनवृद्धि किस सेवा नियम के अंतर्गत स्वीकृत हुई? पदोन्नति किस विभाग ने दी? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है, तो रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में संकोच कैसा?

सेवा पुस्तिका ने फिर खोल दी पुरानी फाइल- जब मत्स्य महासंघ ने सेवा पुस्तिका और निरंतरता प्रमाण-पत्र की मांग की, तब वर्षों पुरानी फाइलें फिर चर्चा में आ गईं, यहीं से एक और प्रश्न पैदा हुआ यदि कर्मचारी वर्षों से राजस्व विभाग में कार्यरत था, तो सेवा पुस्तिका मूल विभाग के पास क्यों नहीं थी? और यदि थी, तो उसका नियमित सत्यापन किसने किया?

संविलियन का सपना...लेकिन मंजिल नहीं मिली?

उपलब्ध दस्तावेजों से यह संकेत भी मिलता है कि राजस्व विभाग में संविलियन का प्रयास हुआ था,यदि ऐसा है,तो क्या वह सफल हुआ? यदि नहीं हुआ, तो फिर प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं हुई? यदि हुआ, तो उसका विधिवत आदेश कहां है? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब केवल सक्षम प्रशासन ही दे सकता है।

'फेविकोल मॉडल' की चर्चा क्यों?

जिले में अब लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं यह सामान्य प्रतिनियुक्ति नहीं, फेविकोल प्रतिनियुक्ति है,एक बार कुर्सी मिली तो फिर उठने का सवाल ही नहीं, बेशक यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं तभी जन्म लेती हैं जब पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है।

- स्टेनो प्रकरण में लगातार उठते सवालों के बीच प्रशासन की चुप्पी बनी सबसे बड़ा रहस्य
- 24 साल की प्रतिनियुक्ति पर 12 खुलासे... फिर भी नहीं टूटी प्रशासन की चुप्पी
- सवालों से नहीं,चुप्पी से घिरा स्टेनो प्रकरण! आखिर शासन क्या छिपाना चाहता है?
- दस्तावेज बोलते रहे...शासन चुप रहा! क्या मौन से बढ़ रहा संरक्षण का संदेह?
- कोरिया का स्टेनो प्रकरण,जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा! आखिर किसके लिए है यह खामोशी?
- चुप्पी क्या साबित करती है? खबरें गलत हैं या जवाब देने की हिम्मत नहीं?
- खबरों के बाद भी न खंडन,न जांच, न जवाब...आखिर किस बात का इंतजार?
- स्टेनो प्रकरण में शासन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाबदेही से बचना ही नया प्रशासनिक मॉडल है?
- प्रतिनियुक्ति 3 से 5 साल की या 24 साल की? मत्स्य विभाग का कर्मचारी, राजस्व विभाग की कुर्सी और शासन-प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी ने खड़े किए बड़े सवाल

क्या व्यवस्था कर्मचारी के लिए है या कर्मचारी व्यवस्था के लिए?

यह पूरा मामला अब केवल एक स्टेनो तक सीमित नहीं है,यह सवाल हर सरकारी कर्मचारी का है, जो नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति पर जाता है, समय पूरा होने पर वापस लौटता है और सेवा नियमों का पालन करता है, यदि किसी मामले में अलग व्यवस्था अपनाई गई,तो उसका आधार क्या था? यदि कोई विशेष प्रशासनिक कारण था,तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

अब जवाब दस्तावेजों से ही आएगा...

इस पूरे प्रकरण में अंतिम निर्णय जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही निकलेगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जब दस्तावेजों के आधार पर इतने गंभीर प्रश्न सार्वजनिक रूप से उठाए जाएं, तो संबंधित विभाग समयबद्ध और तथ्यात्मक उत्तर भी दे, अन्यथा, चुप्पी स्वयं एक प्रश्न बन जाती है, और कोरिया में आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है की क्या यह केवल एक कर्मचारी की कहानी है, या फिर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की, जहां प्रतिनियुक्ति अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी परंपरा बन गई?

दस दिन में तीन चोरियां...फिर भी चोर बेखौफ, पुलिस खामोश!

ठगगवां में लगातार वारदातों से दहशत,शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर उठे सवाल

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत ठगगवां में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है,ग्रामीणों का आरोप है कि महज दस दिनों के भीतर तीन अलग-अलग चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं,लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है,ऐसे में ग्रामीणों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिकायतें केवल थाने की फाइलों तक सीमित रह गई हैं, या वास्तव में जांच भी शुरू हुई है? प्राप्त शिकायत आवेदनों के अनुसार अज्ञात चोरों ने अलग-अलग घरों को निशाना बनाया, कहीं नकदी और घरेलू सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है तो कहीं देर रात घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किए जाने की बात कही गई है। पीड़ितों ने पुलिस से जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की है।

रात एक बजे दरवाजा तोड़ने की कोशिश,जागने पर भागे संदिग्ध-एक शिकायतकर्ता ने बताया कि रात लगभग एक बजे कुछ अज्ञात लोग उनके घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे,आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए,जैसे ही घर के सदस्य बाहर निकले,संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए,घटना के बाद परिवार दहशत में है और क्षेत्र में लगातार सक्रिय चोर गिरोह की आशंका जताई जा रही है।

लाखों की चोरी का दावा-दूसरी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि घर से नकदी, कपड़े और अन्य सामान चोरी हो गया,शिकायत के अनुसार चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत लगभग 2 से 3 लाख बताई गई है, पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है।

दस दिन में तीन घटनाएं,रात्रि गश्त पर उठे सवाल- लगातार तीन चोरी की घटनाओं के बाद ग्रामीणों का कहना है कि यदि एक ही पंचायत में इतने कम समय में लगातार वारदातें हो रही हैं तो पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है, ग्रामीण पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया? क्या संदिग्धों से पूछताछ हुई? क्या चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई? क्या वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाई जा रही है? या फिर शिकायत आवेदन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया?

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप- ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की लगातार घटनाओं की जानकारी पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, इसके बावजूद यदि अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है, लोगों का कहना है कि जब चोर लगातार सक्रिय हैं और अब तक पकड़ से बाहर हैं, तब आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर किस पर भरोसा करें।

अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी निगाहें- ग्रामीणों ने खड़गवां पुलिस से मांग की है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए तथा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाकर संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए, फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि खड़गवां पुलिस इन शिकायतों पर प्रभावी जांच शुरू करती है या चोरी की शिकायतें थाने की फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगी, पुलिस की चुप्पी और अब तक सामने नहीं आई कार्रवाई ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है।

देसी लुक में छाईं अवनीत कौर

गुलाबी सलवार-सूट में दिखीं बेहद खूबसूरत

एक्ट्रेस अवनीत कौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ वह अपने कमाल के फैशन सेंस और बोल्ड चॉइस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में अवनीत ने इंस्टाग्राम पर एथनिक लुक में कुछ बेहद शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।तस्वीरों में अवनीत कौर ने गहरे गुलाबी रंग का पारंपरिक सलवार-सूट पहने नजर आ रही हैं। उनके कुर्ते के नेकलाइन और स्लीव्स पर गोल्डन जरी और गोटा-पत्ती का हैवी वर्क है,जो उन्हें एक रॉयल लुक दे रहा है।इसके साथ ही अवनीत ने मैचिंग की नेट की चुनरी कैरी की है, जिस पर छोटी-छोटी चमकीली बूटियों का काम है। पटियाला स्टाइल सलवार और स्लीव्स पर बने कट-डिज़ाइन उनके पूरे आउटफिट को पारंपरिक होने के साथ-साथ ट्रेंडी और मॉडर्न टच दे रहे हैं।अवनीत का हेयर स्टाइल उनके इस देसी लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उन्होंने अपने बालों को हाफ-अप, हाफ-डाउन स्टाइल में ट्विस्ट करके पीछे पिन किया हुआ है, जबकि बाकी के बालों को सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला छोड़ दिया है।मेकअप की बात करें तो उन्होंने ग्लोइंग बेस के साथ न्यूड विंड आईलाइनर, पिंक ब्लश और ग्लॉसी लिप्स चुने हैं। माथे पर लगी एक छोटी सी काली बिंदी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।

90 के दशक के फिल्म में 90 के दशक के आखिरी दौर की अनोखी झलक

डायरेक्टर राजेश करना की बहुप्रतीक्षित तेलुगु इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर न्यूटनस थर्ड लॉ (जिसमें एक्टर सुमंत मुख्य भूमिका में हैं) के मेकर्स ने फिल्म का एक रोमांचक ट्रेलर रिलीज़ किया है, जिससे फैंस और फिल्म प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेलुगु स्टार नागार्जुन ने अपने एक्स टाइमलाइन पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा,न्यूटनस थर्ड लॉ अब रिलीज़ हो गई है! हर एक्शन का एक नतीजा होता है कितनी सच बात है!! 31 जुलाई से सिनेमाघरों में। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि कहानी 1999 के दौर की है। एक वॉयस-ओवर में कहा जाता है,अभी भी आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। एक पुलिस ऑफिसर सुमंत से कहता हुआ दिखाई देता है,यह एक एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन हमें नहीं पता कि यह एक्सीडेंट है या मर्डर। इसके बाद, वासुदेव का किरदार निभा रहे सुमंत को एक व्यक्ति से पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है,कल रात असल में क्या हुआ था? इस बीच,कॉलेज में पढ़ने वाले दो युवक फोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं,जिनमें से एक दूसरे को बताता है कि एक छोटा सा काम है और अगर वे इसे पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। फिर ट्रेलर में एक व्यक्ति को रिवॉल्वर पकड़े हुए यह कहते हुए दिखाया जाता है,कहते हैं कि चावल के हर दाने पर उसे खाने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है। अगर यह सच है,तो गोलियों पर भी उन लोगों के नाम लिखे होंगे जिनकी वे जान लेंगी। ट्रेलर से यह भी पता चलता है कि जगपति बाबू मर्करी नाम का किरदार निभा रहे हैं। उन्हें लोगों को गोली मारकर मारते हुए दिखाया गया है,जबकि सुमंत, जो कई अपराधों की जांच कर रहे हैं, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे आपस में जुड़े हैं और अगर हाँ, तो कैसे। कुल मिलाकर,ट्रेलर से यह आभास होता है कि फिल्म एक दिलचस्प और समझदारी भरी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर होगी। फिल्म में सुमंत यार्लागड्डा और जगपति बाबू के अलावा अवसारला श्रीनिवास,रवि वर्मा, शेली एन कुमार,त्रिनाद वर्मा, नेहा पठान, पंडित गौतम, हरिनी राव गगनम, रूपेश मरापु और अभिनया सहित कई कलाकार शामिल होंगे। राजेश कर्ण द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण हरीश कोहिरकर ने किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी वेद व्यास गोट्टीपति की है। फिल्म का संगीत सिंजिथ येरामिली का है और संपादन अनिल पासाला का है। फिल्म में स्टंट्स को विंग चुन अंजी ने कोरियोग्राफ किया है।

सनी देओल की बटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी

सनी देओल की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म बटवारा 1947 लंबे समय से लोगों का ध्यान खींच रही है। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित ये फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में आ रही है। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के हवाले किया था,जहां से उन्हें हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने बटवारा 1947 को बिना किसी काट-छांट के मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिल्म बटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के प्रमाणपत्र मिल गया है। इसके बाद ये 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। विभाजन के समय पर आधारित यह फिल्म लाहौर के एक मुस्लिम परिवार की कहानी बयां करती है, जिनका सामना एक हिंदू महिला से होता है, जो वहां मौजूद अपना पैतृक घर छोड़ने से मना कर देती है। फिल्म में सनी के साथ मुख्य किरदार में प्रीति जिंटा दिखाई देंगी। वह 5 साल से भी ज्यादा समय बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं। शबाना आजमी,करण देओल,अली फजल,अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी अहम किरदारों में शामिल हैं। फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है,जबकि गीत जावेद अख्तर ने द्वारा लिखे गए हैं। बटवारा 1947 की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 के साथ होगी।

रिलीज होते ही बनी नंबर-1

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा उत्साह देखने को मिलता है। खासकर साउथ सिनेमा की ऐसी फिल्में जो सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती हैं, उन्हें दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई एक नई साउथ फिल्म ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर यह फिल्म आते ही नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 पर पहुंच गई है। इस फिल्म का नाम कॉन सिटी है, जिसमें साउथ अभिनेता अर्जुन दास मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी, किरदारों की दिलचस्प अदाकारी और कॉमेडी अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि रिलीज के कुछ ही समय बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। कॉन सिटी की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो छोटे-मोटे घोटाले और चालाकी भरे काम करने के लिए जाना जाता है। इस परिवार में बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी अपनी-अपनी तरकीबों से लोगों को प्रभावित करते हैं और पैसे कमाने के नए तरीके तलाशते रहते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह परिवार का हर सदस्य अपनी अलग सोच और हुनर के साथ काम करता है।

अमाल मलिक ने तनिष्क बागची के खिलाफ अपने भड़काऊ पोस्ट किए डिलीट

सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक ने तनिष्क बागची के खिलाफ अपने तीखे पोस्ट हटा दिए हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने आरोपों से पीछे नहीं हट रहे हैं। सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक अपने साथ कलाकार म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची के खिलाफ जो तीखे पोस्ट किए थे उसे अब डिलीट कर दिया है। हालांकि, म्यूजिशियन ने साफ किया कि पोस्ट हटाने का मतलब यह नहीं है कि वह अपने लगाए गए आरोपों को वापस ले रहे हैं। बल्कि इसके बजाय, उन्होंने कहा कि वह बस अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन से कचरा हटाना चाहते थे।26 जुलाई को एक्स पर एक नया बयान जारी करते हुए, अमाल ने साफ किया कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं,बल्कि सिर्फ पोस्ट को आर्काइव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी स्पष्टता के साथ लिया गया है और जोर देकर कहा कि उन्होंने जरूरी कदम उठा लिए हैं।

सिंगर ने किया 10 साल का लंबा सब्र

सिंगर ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से चुप थे और अब जाकर उन्होंने बोलने का फैसला लिया है। उन्होंने लिखा,अपने गुस्से को दबाकर रखने में लगभग 10 साल का लंबा सब्र लगा है। आज,एक दशक बाद, मुझे आवाज उठानी पड़ी क्योंकि कोई भी सही बात के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया है जिन्हें वे घटिया मानते हैं। अमाल ने कहा कि उन्होंने एक बहुत बुरे आदमी के बारे में सच सामने लाने की कोशिश की है और भरोसा जताया कि आखिरकार कर्म का ही फल मिलेगा। उन्होंने तनिष्क को सीधी चेतावनी भी दी और हिंदी में लिखा,बेटे,मुझसे तो औकात में ही रहना और इसे जीवन भर की चेतावनी बताया।

अमाल मलिक ने तनिष्क बागची पर उठाए सवाल

बता दें कि इससे पहले, भी अमाल ने तनिष्क पर म्यूजिक कॉपी करने और दूसरों के काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर धमकाया जा रहा था।

खेल समाचार

4 दिन में इंडिया ने जीते 3 मुकाबले

टीम इंडिया ने किया जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली ट्रॉफी आई,भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी 20 में एकतरफा अंदाज में हराकर,सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है...

हरारे,26 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार लगातार 2 सीरीज की हार के बाद जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर कोई सीरीज अपने नाम कर ली है। 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 35 रन से जीत दर्ज की और मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में सीरीज हार का सामना करने वाली कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट चुकी है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 192 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना पाई।

टीम इंडिया ने बनाए 192 रन

इससे पहले टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक अर्धशतक की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए हैं। भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। अभिषेक फिर फ्लॉप रहे और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव और तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन ने पारी को संभाला। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 गेंदों पर 75 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 95 तक पहुंचाया। ईशान दूसरे विकेट के रूप में 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए।

वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल

वैभव ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े, जब ऐसा लग रहा था कि वैभव अपना पहला टी20 शतक पूरा कर लेंगे, उसी समय वह 81 के स्कोर पर आउट हो गए। वैभव का यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था। 49 गेंदों की इस पारी में वैभव ने 4 छक्के और 8 चौके लगाए।

श्रेयस अय्यर बड़ी पारी से चूके

श्रेयस अय्यर अच्छी शुरुआत को एक बार फिर बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। भारतीय कप्तान 18 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 9 गेंदों पर नाबाद 11 और रिंकू सिंह ने 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट पर 192 तक पहुंचाया। रिंकू पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1, ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1, वेस्ली मधेवेरे ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1, और ब्रैड इवांस ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए।

महिला हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम

टोक्यो,26 जुलाई 2026। ओलंपिक 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम को ऐतिहासिक प्रदर्शन तक पहुंचाने वाले कोच स्योर्ड मारिजने अब आगामी एफआईएच हॉकी महिला वर्ल्ड कप पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मारिजने का मानना है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है और खिलाड़ियों की तैयारियां लगातार मजबूत हो रही हैं। अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होने वाले एफआईएच हॉकी महिला वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। टीम का मुख्य फोकस फिटनेस स्तर को बेहतर बनाने, मैदान पर टैक्टिकल अनुशासन बनाए रखने और गोल करने के मौकों को सफलतापूर्वक भुनाने की क्षमता बढ़ाने पर है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 : ऋषिकंत ने वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर और तोड़ा रिकॉर्ड

ग्लासगो,26 जुलाई 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एक और मेडल अपने नाम किया। रविवार को वेटलिफ्टर ऋषिकंता सिंह चनंबम ने पुरुषों के 60 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय वेटलिफ्टर ने कुल 264 किग्रा वज़न उठाया। उन्होंने स्नैच राउंड में रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया और मलेशिया के बिन क्सदान मोहम्मद अनिक के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि केन्या के जोशुआ अमूंगा म्बोया ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआत 116 किग्रा से की, फिर 119 किग्रा और तीसरे प्रयास में 121 किग्रा वज़न सफलतापूर्वक उठाया,जिससे वे स्नैच राउंड में सबसे आगे रहे। अपने आखिरी स्नैच प्रयास में 121 किग्रा वज़न उठाकर ऋषिकंता ने स्नैच में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। इसी लय को क्लीन एंड जर्क राउंड में भी बनाए रखते हुए, ऋषिकंता ने 143 किग्रा वज़न सफलतापूर्वक उठाकर मेडल की दौड़ में अपनी स्थिति मज़बूत की। उनका पहला प्रयास संयमित और तकनीकी रूप से बेहतरीन था,जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहे। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे प्रयास में 148 किग्रा वज़न उठाने का फैसला किया,लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए, जिससे अनिक को बढ़त बनाने का मौका मिल गया। मलेशियाई खिलाड़ी ने 149 किग्रा वज़न सफलतापूर्वक उठाकर इसका जवाब दिया। आखिरी प्रयास में, ऋषिकंता ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 151 किग्रा वज़न उठाने की कोशिश की। उन्होंने वज़न को अपने कंधों तक तो उठा लिया,लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जर्क पूरा नहीं कर पाए, और इस तरह कुल 264 किग्रा के साथ उनकी चुनौती समाप्त हो गई। अनिक, जिनकी जीत पहले ही तय हो चुकी थी,ने क्लीन एंड जर्क में 152 किग्रा वज़न उठाकर शानदार अंदाज़ में समापन किया। इससे उनका कुल वज़न 273 किग्रा हो गया,जो एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड था और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया।

न्यायालय नायब तहसीलदार भैयाथान ,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /ब/121 वर्ष
ग्राम -कुसमुसी पह0न0-11

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सूरज लाल पिता राजू जाति कंवर निवासी ग्राम कुसमुसी पह0न0-11 रा0नि0म0 भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा पेश किया गया है कि आवेदक अपने स्वयं सूरजलाल का जन्म दिनांक 30/06/2006 को ग्राम कुसमुसी मे हुई है अज्ञानतावश जन्म पंजियन नहीं करा पाया है आवेदक अपने स्वयं का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 03/08/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।

आज दिनाँक 20/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील **कार्यपालिक दण्डाधिकारी भैयाथान,जिला-सूरजपुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका गिरजा प्रसाद गुप्ता आ0 / पति स्व0 रामदेव प्रसाद केशरवानी जाति, निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला न्यू महामाया रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2559/1, 2602/99 रकबा 0.02 1/4, 0.04 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 10.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग में फिर विवादित पदोन्नति! नई सूची से पहले शिकायतों का अंबार,केंद्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप

सीधी भर्ती छोड़ प्रमोशन क्यो...फूड सेफ्टी ऑफिसर पदोन्नति पर वैधानिकता के सवाल,मुख्यमंत्री से जांच की मांग...

- फूड सेफ्टी ऑफिसर पदोन्नति पर नया विवाद,नमूना सहायकों को प्रमोशन के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत,नई सूची पर रोक की मांग
- क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर पदोन्नति नियमों के दायरे में...केंद्रीय कानून का हवाला देकर मुख्यमंत्री से स्वतंत्र जांच की मांग...
- खाद्य विभाग में फिर 'विवादित प्रमोशन' की आहट! नमूना सहायकों को एफएसओ बनाने पर फिर सवाल, नई सूची जारी होने से पहले जांच की मांग
- फूड सेफ्टी ऑफिसर पदोन्नति पर फिर बवाल केंद्रीय नियमों के विपरीत प्रमोशन का आरोप,मुख्यमंत्री से स्वतंत्र जांच और पदोन्नति पर रोक की मांग
- पहले भी 'नमूना सहायकों को पदोन्नति' को लेकर उठा था विवाद,अब मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में केंद्रीय कानून और नियमों का हवाला

न्यूज डेस्क

रायपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) के पद पर नमूना सहायकों को पदोन्नति दिए जाने का विवाद एक बार फिर चर्चा में है,विभाग में नई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी होने और नई पदोन्नति सूची कभी भी जारी होने की संभावना के बीच मुख्यमंत्री को विस्तृत शिकायत भेजकर पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने तथा आगामी पदोन्नति आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है,यह पहला अवसर नहीं है जब विभाग की इस पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठे हों,दैनिक घटती-घटना ने पूर्व में भी प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर नमूना सहायकों को फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर पदोन्नति देने,पदोन्नति कोटा बढ़ाने तथा भर्ती नियमों में किए गए बदलावों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए थे,अब एक बार फिर वही मुद्दा शिकायत के रूप में शासन तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में क्या कहा गया है?

मुख्यमंत्री को भेजे गए आवेदन में शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 37 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 2.1.3 के अंतर्गत एक वैधानिक पद है, इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों से निर्धारित होती है, शिकायत में भारत सरकार के 16 जनवरी 2023 के राजपत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि नियम 2.1.2 में अभिहित अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता और पांच वर्ष के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुभव का स्पष्ट प्रावधान किया गया है,जबकि नियम 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन प्रावधानों में नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

वर्ष 2021 से लगातार हो रही पदोन्नति पर सवाल

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2021 से लगातार नमूना सहायकों को पदोन्नति देकर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनाया जा रहा है,इसके लिए वर्ष 2021, 2024, 2025 और 2026 में अलग-अलग पदोन्नति आदेश जारी किए गए। इतना ही नहीं, 02 जून 2026 को पुनः विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर एक और पदोन्नति सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि पूरी प्रक्रिया की वैधानिकता पर पहले से सवाल उठ रहे हैं,तो नई सूची जारी करने से पहले स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

सीधी भर्ती की जगह पदोन्नति क्यों?

मामले का दूसरा बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है,शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में योग्य युवा फूड सेफ्टी ऑफिसर की सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं,यदि रिक्त पदों को लगातार पदोन्नति से भरा जाएगा तो नई भर्ती के अवसर कम हो जाएंगे और योग्य अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर ही समाप्त हो सकता है, इसी कारण शिकायत में कहा गया है कि जहां सीधी भर्ती संभव है, वहां बार-बार पदोन्नति को प्राथमिकता देने के औचित्य की भी जांच होनी चाहिए।

पदोन्नति कोटा बढ़ाने पर भी उठे सवाल

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 05 मई 2026 के माध्यम से पदोन्नति कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह जांच का विषय है कि यह संशोधन केंद्रीय अधिनियम और नियमों के अनुरूप है या नहीं तथा इसका सीधी भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियों की जांच की मांग...

मुख्यमंत्री को भेजे गए आवेदन में मांग की गई है कि वर्तमान में पदोन्नति प्राप्त सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यताओं की जांच कराई जाए,विशेष रूप से यह परीक्षण किया जाए कि संबंधित विषयों में निर्धारित डिग्रियां उपलब्ध हैं या नहीं,दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त डिग्रियों की वैधानिक मान्यता क्या है,यूजीसी की मान्यता प्राप्त है या नहीं, विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया था या नहीं।

बार-बार डीपीसी क्यों?

शिकायतकर्ताओं ने यह भी प्रश्न उठाया है कि दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद कुछ ही महीनों में पुनः जून 2026 में डीपीसी बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी,उनका कहना है कि यदि रिक्तियां पहले से उपलब्ध थीं तो एक ही प्रक्रिया में उन्हें भरा जा सकता था,ऐसे में लगातार डीपीसी आयोजित करने के कारणों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद क्यों है महत्वपूर्ण?

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर केवल निरीक्षण करने वाला अधिकारी नहीं होता, बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन,खाद्य नमूनों की जांच,अभियोजन की कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है,विशिष्ट अवसरों पर उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के भोजन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है,इसी कारण शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस पद पर नियुक्ति पूरी तरह विधिसम्मत,पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

स्वतंत्र जांच की मांग

- प्रस्तावित एवं लंबित सभी पदोन्नति आदेशों और जॉइनिंग पर जांच पूरी होने तक अंतरिम रोक लगाई जाए।
- पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- नमूना सहायकों को फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर पदोन्नति देने की वैधानिकता की जांच की जाए।
- पदोन्नति कोटा 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का विधिक परीक्षण कराया जाए।
- यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन अथवा अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

पहले भी उठा था विवाद,अब फिर वही सवाल- दैनिक घटती-घटना ने पूर्व में प्रकाशित समाचारों में भी यह मुद्दा उठाया था कि विभाग में तकनीकी पदों पर भर्ती व्यवस्था के बजाय पदोन्नति को प्राथमिकता दिए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अब मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में वही मुद्दे विस्तृत रूप से उठाए गए हैं और केंद्रीय कानून, नियमों तथा राजपत्रों का हवाला देते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, अब निगाहें राज्य शासन पर हैं कि शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच कराई जाती है या प्रस्तावित पदोन्नति सूची जारी की जाती है,यदि जांच से पहले नई पदोन्नति होती है, तो इस पूरे मामले के न्यायालय तक पहुंचने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में 'मिशन जल रक्षा' से 2.04 मीटर भूजल स्तर की वृद्धि

राजनांदगांव,26 जुलाई 2026। मानसून के आगमन के साथ ही देशभर में जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी 'कैच द रैन' अभियान को नई गति मिली है। जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जल स्रोतों की स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के जिले वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्यों में जुटे हैं। इस दिशा में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला अपनी अभिनव पहल 'मिशन जल रक्षा' के कारण देशभर में एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, 'मिशन जल रक्षा' के प्रभाव से राजनांदगांव जिले में भूजल स्तर में औसतन 2.04 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पूरे जिले में सिंचाई सुविधाएं बेहतर हुई हैं और पेयजल सुरक्षा भी मजबूत हुई है। मंत्रालय का कहना है कि यह पहल वैज्ञानिक योजना, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिला प्रशासन ने मानसून शुरू होने से पहले ही व्यापक तैयारी पूरी कर ली थी। भूजल पुनर्भरण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए जीआईएस मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) तथा 'रिज-टू-वैली' प्लानिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। इन वैज्ञानिक उपायों के आधार पर ऐसी रणनीति तैयार की गई, जिससे वर्षा की प्रत्येक बूंद का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वैज्ञानिक योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने कई नवाचार किए। लंबे समय से बंद पड़े और अनुपयोगी बोरवेलों को 'रिचार्ज शाफ्ट' में परिवर्तित किया गया। वहीं, कठोर चट्टानी क्षेत्रों में पानी को गहराई तक पहुंचाने के लिए मिनी परकोलेशन टैंकों को गहरे इंजेक्शन कुओं के साथ जोड़ा गया। इन उपायों से भूजल पुनर्भरण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मंत्रालय के अनुसार, 'मिशन जल रक्षा' की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक जनभागीदारी रही है। किसान, महिलाएं, युवा और ग्राम पंचायतें जल संरक्षण एवं जागरूकता अभियानों से सीधे जुड़े। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भूजल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया गया। जिले में लगभग 70 प्रतिशत ग्रीष्मकालीन धान की खेती को कम जल खपत वाली वैकल्पिक फसलों की ओर स्थानांतरित किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने फाफाडीह में युवाओं और आमजनों के साथ सुनी 'मन की बात' की 136वीं कड़ी

'मन की बात' में बार-बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,26 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित दया भवन में युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 136वीं कड़ी का श्रवण किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम देशवासियों के साथ संवाद का एक ऐसा सशक्त मंच बन गया है, जो समाज के बीच हो रहे सकारात्मक और प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। देशभर के लोगों को प्रत्येक माह इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा रहती है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे

व्यक्तियों,संस्थाओं,नवाचारों और जन-अभियानों को सामने लाते हैं,जो बिना किसी प्रसिद्धि या व्यक्तिगत अपेक्षा के समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले कुछ महीनों में 'मन की बात' कार्यक्रम में लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और नवाचारों का उल्लेख किया जाना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले मल्हार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक शक्ति, जनजातीय परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कोरबा में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की उपलब्धियों का राष्ट्रीय मंच पर उल्लेख किए जाने से न केवल छत्तीसगढ़वासियों का उत्साह बढ़ता है, बल्कि राज्य के नवाचारों और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को देशभर में नई पहचान भी मिलती है। 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'कैच द रेन' अभियान के अंतर्गत देशभर में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा में जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को उत्साहजनक बताते हुए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोरबा में वैज्ञानिक पद्धति से जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए भू-स्थानिक मैपिंग,शैलो एक्विफर मैनेजमेंट, रिचार्ज वेल तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य वर्षा जल को अधिकतम मात्रा में संरक्षित करना,भूजल स्तर में सुधार लाना और क्षेत्र में जल उपलब्धता को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से बारिश की प्रत्येक बूंद को सहेजने का जो संदेश दिया है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकता है। जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं,बल्कि मानव जीवन,कृषि,पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है।

कांकेर में मलेरिया से 2 छात्रों की मौत : सरकारी-हॉस्टल में रहने वाले 11 छात्रों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव,कैंप लगाकर इलाज कर रहा स्वास्थ्य अमला

कांकेर,26 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीते दो दिनों में मलेरिया से सरकारी हॉस्टल में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। जबकि दूसरे हॉस्टल में रहने वाले 11 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। प्रभावित छात्रावासों और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रही हैं। मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही सभी छात्रावासों में खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इरादाह और मर्दापोटी

छात्रावास के 11 छात्र मलेरिया पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार,डोमाहर्रा के रहने वाली तीन सगी बहनों को तेज बुखार होने पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें 9 साल की करीना विश्वकर्मा की 25 जुलाई को इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज जारी है। मर्दापोटी छात्रावास में कई छात्रों को बुखार और सिरदर्द की शिकायत हुई थी। जांच में 4 छात्र मलेरिया पॉजिटिव मिले। इनमें 9 साल के छात्र सुभाष कुमेटी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे घर ले गए थे। रविवार सुबह हालत गंभीर होने पर उसे दोबारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त जया मनु ने बताया कि 22 जुलाई को सभी छात्रावासों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई गई थी। उस समय कोई भी बच्चा मलेरिया संक्रमित नहीं मिला था।

छात्र आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार,धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत : दीपक बैज

रायपुर,26 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ग्राम नकटी मामले को लेकर गठित कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू,शिव कुमार डहरिया,विकास उपाध्याय सहित जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने एकजुट होकर संघर्ष किया और पूरे देश के छात्र तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की जीत है। बैज ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सभी छात्रों का आभार व्यक्त किया है। उनका आरोप था कि युवाओं के आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह फैसला लिया। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी छात्रों के साथ थी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)